Centre for Labour Research and Action

Rosa Luxemberg Stiftung-South Asia

कचरा प्रबंधन की हकीकत

घर-घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे प्रवासी जनजातीय परिवारों
की स्थिति पर एक अध्ययन

अनामिका सिंह और पियूष माने

दिसंबर 2023

रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टिफतुंग, दक्षिण एशिया द्वारा समर्थित

आभार

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने उत्तरदाताओं - कचरा संग्रहण कर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो अध्ययन में भाग लेने के लिए सहमत हुए और धैर्यपूर्वक हमें अपने जीवन, अनुभवों और काम के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। हम गुजरात में अनौपचारिक प्रवासी श्रमिकों के राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन मजूर अधिकार मंच का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिसने इस अध्ययन के लिए डेटा संग्रह में हमारा समर्थन किया। उनके समर्थन के माध्यम से हम अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत की बस्तियों में श्रमिकों की पहचान करने और उनके साथ संबंध बनाने में सक्षम हुए। हम विशेष रूप से दिनेश परमार, डेनिस मैकवान, शांतिलाल मीना, भूपत सोलंकी, हिरल परमार, अश्विन वाघेला, मेघा गामित, जयेश गामित, अमूलभाई पवार, योहनभाई पवार, शकील शेख और अखिलेश विहारिया को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे।

इसके अलावा, यह अध्ययन हमारे फंडिंग पार्टनर रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टिफतुंग के अटूट समर्थन को स्वीकार किए बिना पूरा नहीं होगा। हम विशेष रूप से श्री राजीव कुमार और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमेशा सहयोगी रहे हैं और हमारे सभी प्रयासों में हमारा समर्थन किया है।

अंत में, हम सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन में अपने सहयोगियों, विशेषकर हमारे सचिव सुधीर कटियार द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की गहराई से सराहना करते हैं। शुरुआत से लेकर अध्ययन के समापन तक, हमारे सहयोगियों ने अपनी आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि से हमारा समर्थन किया और यह रिपोर्ट उनके इनपुट के बिना संभव नहीं होती।

यह अध्ययन सामूहिक श्रम और सहयोगात्मक प्रयासों से उपजा है। हालाँकि, दोष, यदि कोई हो, पूरी तरह से लेखकों का है।

दिनांक: दिसंबर 2023

अनामिका और पीयूष

डेटा संग्रहण टीम:

दिनेश परमार, डेनिस मैकवान, शांतिलाल मीना, भूपत सोलंकी, हिरल परमार, अश्विन वाघेला, मेघा गामित, जयेश गामित, अमूलभाई पवार, योहनभाई पवार, शकील शेख और अखिलेश विहारिया

तस्वीरें:

अनामिका सिंह और पियूष माने

डिज़ाइन: बिंदु

मुद्रण: अमारा क्रिएशन्स

कचरा प्रबंधन की हकीकत

घर-घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे प्रवासी जनजातीय परिवारों
की स्थिति पर एक अध्ययन

अनामिका सिंह और पियूष माने
दिसंबर 2023

रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टिफतुंग, दक्षिण एशिया द्वारा समर्थित

विषय सूची

प्रस्तावना.....4

सारांश.....6

अध्याय 1: भूमिक.....8

अध्याय 2: मौजूदा साहित्य की समीक्षा.....11

अध्याय 3: भारत में कचरा प्रबंधन के लिए नियामक ढांचा.....16

अध्याय 4: सर्वेक्षण स्थानों पर कचरा प्रबंधन प्रणाली.....20

अध्याय 5: कार्यप्रणाली.....25

अध्याय 6: मुख्य निष्कर्ष और विश्लेषण.....26

अध्याय 7: समापन टिप्पणी और आगे का रास्ता.....49

सन्दर्भ.....54

परिशिष्ट.....56

संक्षिप्ताक्षर:

एएमसी: अहमदाबाद नगर निगम

जीएमसी: गांधीनगर नगर निगम

जीपीएस: ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

एमआरएफ: सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा

आरएफआईडी: रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान

आरटीएस: रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशन

एससी: अनुसूचित जाति

सेवा: स्व-रोज़गार महिला संघ

प्रस्तावना

कचरा हमारे समय के सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकटों में से एक है। अकार्बनिक और गैर-नवीकरणीय सामग्रियों (जैसे प्लास्टिक) से बने या तोड़ने और बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए डिस्पोजेबल उत्पादों की बढ़ती मानव खपत के कारण हाल के दशकों में दुनिया भर में डंपिंग स्थलों पर जाने वाले ठोस कचरे की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

कचरे को अक्सर एक तकनीकी समस्या के रूप में देखा और व्यवहार किया जाता है जिसे पेशेवरों और तकनीकी 'विशेषज्ञों' के रूप में समझे जाने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से हल किया जाता है। फिर भी, कचरा एक अत्यावश्यक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है, साथ ही पारिस्थितिक और तकनीकी भी। शैक्षणिक और नागरिक समाज क्षेत्रों के शोधकर्ताओं ने लंबे समय से ठोस कचरे के साथ ऐसे जुड़ाव की वकालत की है जो इस संकट से निपटने के लिए इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों को उभारता है।

भारत में, जहां मैं अनौपचारिक रिसाइक्लर्स (सड़कों के किनारे, कूड़ेदानों, सामुदायिक कूड़ेदानों और घरों/व्यवसायों से रिसाइकल योग्य सामग्री इकट्ठा करने और बेचने वाले स्व-रोज़गार कार्यकर्ता) और दलित महिला समुदायों के साथ काम करती हूं, वहां लिंग, जाति और वर्गीकृत सामाजिक असमानताएं हैं। कचरा उत्पादन और प्रबंधन अत्यधिक दृश्यमान है और रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार दोहराया जाता है। फिर भी, स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन) के पीछे घोषित समावेशी इरादों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ठोस कचरा प्रबंधन नियमों में 2016 के संशोधन के बावजूद, शहरी ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतिगत दृष्टिकोण में निम्नलिखित का संयोजन शामिल है: तकनीकी विशेषज्ञता और कॉर्पोरेट हित। यहां, देश भर के कई शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप 'नई' कचरा अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में आजीविका से अनौपचारिक श्रमिकों का विस्थापन हो रहा है, जिन पर कॉर्पोरेट का प्रभुत्व है।

गुजरात राज्य में, जहां यह रिपोर्ट स्थित है, कोविड -19 महामारी ने शहरी अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के लिए श्रम बल में बदलाव को प्रेरित किया, क्योंकि अपेक्षाकृत नई पीपीपी प्रणाली का दायरा व्यापक हो गया और लॉकडाउन के माध्यम से अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं को और अधिक वैधता प्राप्त हुई। महामारी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां निजीकृत कचरा संग्रहण प्रणाली का यह विस्तार निर्माण स्थलों पर काम रुकने के साथ-साथ हुआ, जहां क्षेत्रीय प्रवासी श्रमिकों को नियोजित किया गया था। आमतौर पर शहरी निर्माण कार्य में शामिल, कचरा संग्रहण मौसमी प्रवासी मजदूरों के लिए एक नया क्षेत्र है और इस उभरते क्षेत्र में उनके श्रम अनुभवों के बारे में बहुत कम जानकारी है।

यही कारण है कि सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (सीएलआरए) कचरा श्रम के मुद्दों में शामिल हो रहा है और कचरा क्षेत्र में चल रहे इन बदलावों को समझने में एक महत्वपूर्ण अभिनेता है। सीएलआरए के पास पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी सीमावर्ती इलाकों से शहरों में आने वाले मौसमी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को संगठित करने और उनकी वकालत करने का एक दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण अनुभव है। मैं पहली

बार सुधीर कटियार से 2023 में मिली जब उन्होंने मुझे अहमदाबाद में अपने कई सहयोगियों से मिलवाया, क्योंकि मेरे काम और टिप्पणियों ने मुझे घर-घर कचरा संग्रह और यात्राओं में प्रवासी श्रमिकों की नई और अत्यधिक दृश्यमान प्रमुखता के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए प्रेरित किया।

जब मैंने अहमदाबाद में सीएलआरए कार्यालय का दौरा किया, तो हमने श्रमिकों के अनुभवों और वर्तमान कचरा प्रबंधन प्रणाली में अंतर्निहित शोषण को समझने की दिशा में किए जाने वाले शोध की आवश्यकता पर चर्चा की। श्रमिकों के साथ बात करना, श्रमिक बस्तियों में संबंध बनाना, और श्रमिकों और उनकी मुख्य चिंताओं के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी स्थापित करना, शहरी कचरा संग्रह सेवाओं में शामिल प्रवासी श्रमिकों को संगठित करने और उनकी वकालत करने के सीएलआरए के बड़े लक्ष्य को शुरू करने के लिए हम सभी सहमत थे। अंत में, यह देखते हुए कि इस नए प्रकार के कचरा संग्रहण कार्य में लगे कार्यबल में आदिवासी समुदायों के परिवार समूह/जोड़े शामिल हैं, इस श्रम के जाति, प्रवासन और लिंग संबंधी पहलुओं की तात्कालिकता और श्रमिकों की रहने की स्थिति के साथ अंतर्संबंध को समझने की विशेष रूप से अत्यावश्यक हैं।

यह कार्य-उन्मुख रिपोर्ट अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में इस कार्य में शामिल लोगों और परिवारों के बारे में एक महत्वपूर्ण आधारभूत सर्वेक्षण और जानकारी प्रदान करने में इस कार्य को आरंभ करने का काम करती है। यह अध्ययन इस क्षेत्र में श्रमिकों को संगठित करने और उनके अधिकारों की वकालत करने की सीएलआरए की योजना में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। यह रिपोर्ट स्थानीय अनौपचारिक/अनुबंध श्रम प्रणालियों का विस्तृत विवरण और श्रमिकों के बारे में समग्र डेटा प्रदान करती है ताकि आगे के शोध और विश्लेषण का समर्थन किया जा सके। भारत के कचरा क्षेत्र में उभरते प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे और राजनीति को उभारा जा सके। लिंग, श्रम और सामाजिक प्रजनन के अंतर्संबंधों पर रिपोर्ट का विशेष ध्यान सीएलआरए के काम और सक्रियता को सूचित करने वाली केंद्रीय चिंता के रूप में देखना महत्वपूर्ण और उत्साहजनक है।

यह वैश्विक कचरा संकट को समझने और इसमें हस्तक्षेप करने और कचरे के सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों से निपटने और उन्हें संबोधित करने के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण विकसित करने का एक जरूरी समय और स्थान है क्योंकि यह पूंजीवादी, पितृसत्तात्मक, जातीय और औपनिवेशिक शोषण से संबंधित है और जलवायु, महामारी और आर्थिक संकट के इस समय में उन्हें मजबूत करता है।

जोसी विट्मर, पीएचडी।
पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च फ़ेलो
यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉज़ेन
जोसी ने कचरा आपूर्ति श्रृंखला श्रमिकों पर व्यापक शोध किया है

सारांश

इस अध्ययन का उद्देश्य गुजरात के तीन शहरों - अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले श्रमिकों की स्थितियों को उजागर करना है, जिसमें व्यवसाय के लिंग आधारित पहलू पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये श्रमिक, जो गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी प्रवासी हैं, अनौपचारिक और असंगठित कार्यबल का हिस्सा हैं, जिन्हें शहरी क्षेत्रों में कचरा संग्रहण और पृथक्करण का आवश्यक कार्य करने के बावजूद 'अकुशल' माना जाता है। भारत में कचरा प्रबंधन के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत बढ़ते निजीकरण को देखते हुए, वे सरकार द्वारा सीधे काम पर रखे जाने के बजाय निजी संस्थाओं के साथ मौखिक अनुबंध के तहत काम करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, कचरा प्रबंधन कर्मियों को उनकी दलित पहचान और कचरे के बारे में सामाजिक धारणाओं के कारण उत्पीड़न और कलंक का सामना करना पड़ा है। जाति-आधारित सामाजिक व्यवस्था में, यह भेदभाव अन्य समूहों तक भी फैलता है जो कचरे का काम करते हैं। हालाँकि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 मौजूद हैं, लेकिन इनमें कचरा प्रबंधन श्रमिकों के अधिकारों पर कोई महत्वपूर्ण खंड नहीं है। उनके काम की खतरनाक प्रकृति के बावजूद, श्रमिकों को भविष्य निधि, चिकित्सा बीमा या पेंशन जैसे कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता है। जबकि कचरा प्रबंधन कार्य में कई व्यवसाय शामिल हैं जैसे कि सड़क पर सफाई करना, कचरा उठाना, घर-घर जाकर कचरा एकत्र करना और विशिष्ट कामकाजी परिस्थितियों और चुनौतियों के साथ कचरा अलग करना, यह शोध अध्ययन अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले प्रवासी आदिवासी परिवारों की कामकाजी और रहने की स्थिति पर केंद्रित है। यह अध्ययन श्रमिकों, विशेष रूप से महिला

श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर प्रकाश डालता है, जो घरेलू खाघ कचरा, स्वच्छता कचरा, जैव-चिकित्सा कचरा आदि जैसी विभिन्न सामग्रियों को छानने के कारण कचरे के सीधे संपर्क में आते हैं। ये श्रमिक यूनियनों या सहकारी समितियों जैसे समूहों में संगठित नहीं हैं, जो उनकी कमजोरियों को बढ़ा देता है। कचरा प्रबंधन कार्यकर्ताओं, विशेषकर कूड़ा बीनने वालों के समुदाय पर कई अध्ययन किए गए हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र में आदिवासी महिला प्रवासी श्रमिकों की विशिष्ट स्थितियों का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एक नया व्यवसाय है जिसे पूरे भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा निजी अनुबंधों के तहत अनुबंधित किया जा रहा है जो इस कार्यबल के प्रति राज्य की जवाबदेही को कम करता है। तेजी से शहरीकरण और ग्रामीण से शहरी प्रवास की वर्तमान स्थिति में, शहरी स्थिरता, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने में इन श्रमिकों की भूमिका पर बहस नहीं की जा सकती है। हालाँकि, भारतीय समाज में जाति पदानुक्रम और कचरे से जुड़ा कलंक इन श्रमिकों को कमजोर स्थिति में रखता है। एक संगठित कार्यबल की आवश्यकता है जो सामूहिक रूप से श्रम अधिकारों और सम्मान की मांग कर सके। इस प्रकार, यह अध्ययन गुजरात के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन श्रमिकों को संगठित करने के सीएलआरए के प्रयासों की शुरुआत के रूप में कार्य करता है।

अध्याय 1

कचरा प्रबंधन की हकीकत

भूमिका

जैसे ही कोई गुजरात की राजधानी गांधीनगर में थर्मल पावर स्टेशन के पास पहुंचता है, धुआं उगलती कोयले से चलने वाली इकाइयों के रूप में तीन ऊंची संरचनाएं दिखाई देती हैं। जहरीले रसायनों और दूषित हवा से घिरे इस जगह पर रहने की कल्पना करना कठिन है। इसके बावजूद, पावर स्टेशन के पीछे शहर में घर-घर कचरा संग्रहण के काम में लगे प्रवासी श्रमिकों की एक बस्ती है। ये श्रमिक भारत में कचरा प्रबंधन क्षेत्र में लगे लगभग चार मिलियन श्रमिकों की श्रम शक्ति का हिस्सा हैं। भारत में प्रति वर्ष बासठ मिलियन टन कचरा पैदा होता है, लेकिन विश्व बैंक के अनुसार यह आंकड़ा लगभग 277 मिलियन टन है (मजूमदार, 2023)।

'विश्व स्तरीय शहर' बनाने के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी और विविधता के कारण कचरा प्रबंधन के विचार ने नए आयाम ले लिए हैं, जो विनिमय के लिए वैश्विक गंतव्य बनने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया ने अनिवार्य रूप से शासन प्रणाली और श्रम तंत्र में बदलाव लाया है, खासकर शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन से निपटने के दौरान, जिसमें सड़क की सफाई, कचरा उठाना, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे की छंटाई प्रसंस्करण केंद्र, और पुन: प्रयोज्य या पुनर्चक्रण योग्य कचरे का प्रसंस्करण और बिक्री जैसे व्यवसाय शामिल हैं (जोस्युला एट अल., 2022)। कार्य अनुबंधों की प्रकृति भी अलग-अलग होती है, जिसमें सरकारी-नियुक्त सफाई कर्मचारी, निजी अनुबंध पर घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र में कचरा बीनने वाले विविध कार्यबल का हिस्सा होते हैं। यह परिकल्पना की गई है कि विकासशील देशों में, लगभग एक से दो प्रतिशत आबादी, ज्यादातर शहरी गरीब, अनौपचारिक कचरा प्रबंधन कार्य में लगे हुए हैं, स्थायी कचरा प्रबंधन में स्थानीय सरकारों के लिया काम करते हैं (चतुर्वेदी एट अल। 2015 जैसा कि कानेकल, 2019 में उद्धृत किया गया है) ;माधव, 2010).

कचरा प्रबंधन कर्मचारी अक्सर स्थायी या नियमित श्रमिकों के रूप में नियुक्त होने के बजाय अनौपचारिक कार्य अनुबंध या स्व-रोज़गार में लगे होते हैं, जिससे विभिन्न चुनौतियाँ और कमजोरियाँ पैदा होती हैं। इन श्रमिकों को अपने काम की प्रकृति और वित्तीय चुनौतियों के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, लिंग, जाति, धर्म, प्रवासन स्थिति और भाषा जैसी पहचानें हाशिए की परस्पर परतों को जोड़ती हैं। कार्य की यह अनौपचारिकता और अनिश्चित प्रकृति शोषण और सम्मानजनक जीवन और आजीविका के लिए ख़तरे का कारण बनती

है। इसके अलावा, काम छोड़ने के सीमित रास्ते हैं क्योंकि यह जन्म के समय दी गई जाति आधारित पहचान पर निर्भर है। तेजी से शहरीकरण की शुरूआत और निजीकरण के नेतृत्व में शहरीकरण के हालिया रुझानों ने कचरा प्रबंधन को एक तकनीकी-प्रबंधकीय मुद्दा बना दिया है, इसे उस सामाजिक गतिशीलता से अलग कर दिया है जिसने इसे लंबे समय से निर्देशित किया है। इससे पता चलता है कि कचरा प्रबंधन को केवल पर्यावरण संरक्षण की एक सूचित विधि के रूप में देखने से अक्सर 'सामाजिक' की अनुपस्थिति हो सकती है जिसके लिए पर्यावरण की रक्षा की जानी है और जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करती है (विट्मर, 2022)। एक अन्य आयाम जो राज्य द्वारा कचरा प्रबंधन श्रमिकों के साथ व्यवहार को आकार देता है, वह है काम को 'अकुशल' करार देना। तथाकथित 'अकुशल' कचरा कार्य के क्षेत्र में कौशल को समझने पर राजेंद्र (2022) का अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कचरा कार्य के भीतर कौशल सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से अर्जित और सीखे जाते हैं, लेकिन नौकरशाही द्वारा 'अकुशल' के रूप में वर्गीकृत और अवमूल्यन किया जाता है। राजेंद्र का तर्क है कि "'कुशल' कार्य राजनीतिक और सामाजिक रूप से निर्मित और भौतिक रूप से आकस्मिक है।" कचरे से निपटने के लिए विभिन्न इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के संदर्भ में काम में अभ्यस्त होने की बाध्यता से श्रमिकों के शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने का संकेत मिला। 'अकुशल' के रूप में वर्गीकरण से उन्हें काम के लिए मिलने वाली मज़दूरी भी प्रभावित होती है (हेसलोप और जेफ़री, 2020 जैसा कि राजेंद्र, 2022 में उद्धृत किया गया है)। इसलिए, अन्य प्रासंगिक प्रश्नों के बीच पहुंच के अस्थायी-स्थानिक पहलू को संबोधित करते हुए कचरे का प्रबंधन स्वाभाविक रूप से श्रम और सामाजिक सुरक्षा के सवालों से जुड़ा हुआ है।

इस रिपोर्ट को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसकी शुरूआत अध्ययन के संदर्भ और मौजूदा साहित्य के परिचय से होती है, इसके बाद कचरा प्रबंधन, कचरा की मूल्य श्रृंखला से संबंधित नियामक ढांचे की समझ और कचरा प्रबंधन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसके बाद, अध्ययन की पद्धति की व्याख्या की गयी है, उसके बाद अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों के बारे में बताया गया है, ताकि अंत में समापन टिप्पणी पर पहुंचा जा सके और आगे का रास्ता निकाला जा सके।

अध्याय 2

मौजूदा साहित्य की समीक्षा

भारत में कचरा प्रबंधन प्रणाली जाति व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। यह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों और सामाजिक समूहों के शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है (महालिंगम, जगन्नाथन और सेल्वराज 2019; रोड्रिग्स 2009 जैसा कि राजेंद्र, 2022 में उद्धृत किया गया है; पाल, 2023)। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में, "प्रदूषणकारी" कार्य दलितों को सौंपे जाते हैं। आधुनिकीकरण के तहत इसे संस्थागत बनाया गया, जिसने जाति के आधार पर इस उत्पीड़न को "मजदूरी व्यवसायों" में बदल दिया (श्रुति और मजूमदार,

2021)। अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है (बीएडब्ल्यूएस, खंड 1, पृष्ठ 47), जो कचरा प्रबंधन कार्य के मामले में भी सच है।

दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच जैसे संगठनों ने भारत में कचरा संग्रहण में लगे श्रमिकों की स्थिति के प्रति राज्य के उदासीन रवैये के बारे में चिंता जताई है, जो श्रमिक ज्यादातर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं (DASAM, 2022)। जबकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दलित इस प्रणाली की रीढ़ बने हैं, तेजी से आदिवासी समुदाय भी इस व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं (अरोड़ा, 2018)। ये कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि प्रत्येक उत्पादन, वितरण और उपभोग प्रक्रिया के बाद उत्पन्न कचरे का निपटान स्थायी रूप से किया जाए। हालाँकि, उनके योगदान को स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले छोर पर धकेल दिया गया है।

भारत में कचरा प्रबंधन क्षेत्र सीमित तकनीकी नवाचारों के साथ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। कचरा की मूल्य श्रृंखला में श्रमिकों की भूमिका को निर्धारित करने का आधार जाति है। अध्ययनों ने यह भी उजागर किया है कि दलितों के प्रति यह असम्वेदनशील दृष्टिकोण ही प्रमुख कारण है कि नगरपालिका सरकारों ने अनौपचारिक कचरा प्रबंधन क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की है (चंद्रन एट अल।, 2009 जैसा कि कानेकल, 2019 में उद्धृत किया गया है)। इस अनौपचारिकता के कारण यह संकेत दिया गया कि मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। जाति को वह कारक बताया गया है जो भारत में संविदाकरण प्रक्रियाओं और श्रम की अनौपचारिकता को आकार देता है (श्रुति और मजूमदार, 2021)।

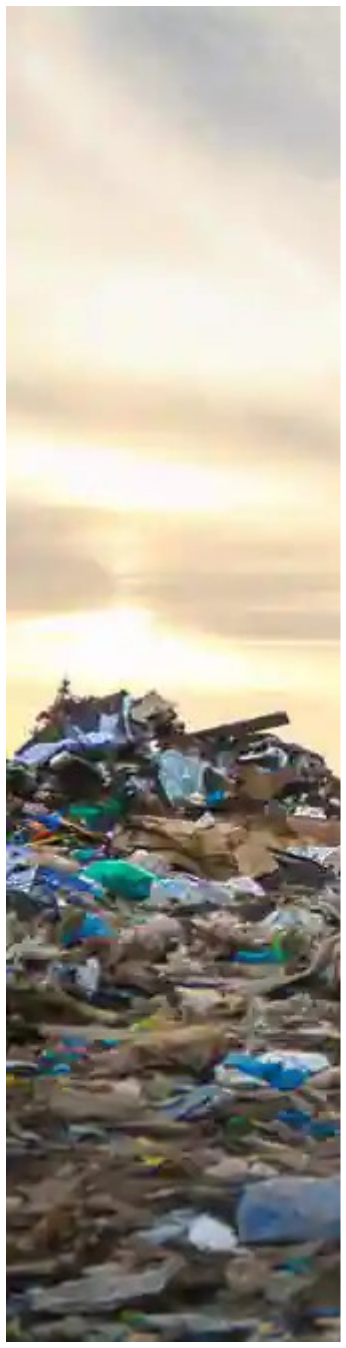

इसके अलावा, जो श्रमिक किसी विशेष क्षेत्र में कचरा प्रबंधन में लगे हुए हैं, वे ज्यादातर अंतरराज्यीय या अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं, जिससे गंतव्य पर उनकी कमजोरियां बढ़ जाती हैं। बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक विकास के प्रतिकूल प्रभावों के कारण उनकी स्थिति और खराब हो गई है। ये श्रमिक गरीब हैं, मात्र निर्वाह योग्य मजदूरी अर्जित करते हैं, और व्यावसायिक खतरों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों से सुरक्षा का भी अभाव है। कार्य की यह अनौपचारिकता और अनिश्चित प्रकृति शोषण और सम्मानजनक जीवन और आजीविका के लिए ख़तरे का कारण बनती है। इसके अलावा, बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से भी उन्हें काफी खतरा है। अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ कूड़ेदानों के करीब अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, उन्हें चरम मौसम की घटनाओं का महत्वपूर्ण जोखिम होता है (ओट्स एट अल।, 2018)। जाति पदानुक्रम में उनकी स्थिति स्वास्थ्य संबंधी खतरों, कार्य असुरक्षा, कम आय और नागरिक अधिकारियों और नागरिकों के हाथों उत्पीड़न जैसी व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करती है। वैकल्पिक आजीविका के अवसर खोजने का विकल्प भी सीमित है और इस प्रकार श्रमिक अंतर-पीढ़ीगत गरीबी के चक्र में फंस गए हैं (चेंगप्पा, 2013 जैसा कि कानेकल, 2019 में उद्धृत किया गया है)।

शोधकर्ताओं द्वारा कचरा प्रबंधन के लैंगिक पहलू का भी

पता लगाया गया है। शहरी भारत में लगभग चार लाख महिलाएँ सीधे तौर पर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन कार्य में लगी हुई हैं (डैश, 2023)। महिला कचरा प्रबंधन कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से कचरा बीनने में लगी महिलाओं और उनके सामने आने वाले लिंग, सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक जोखिमों के संबंध में अध्ययन किए गए हैं। 1990 के दशक में बैंगलोर में एक अध्ययन के अनुसार, कम मजदूरी और स्वास्थ्य जोखिमों के बावजूद, कचरा बीनने से अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित निचली जातियों की महिलाओं को आय का स्रोत मिला। तमिलनाडु में ज्यादातर महिलाएं शादी, रोजगार के अवसरों की कमी और सूखे समेत अन्य कारणों से गांवों से पलायन कर गईं।

स्वच्छता श्रम में लगी दलित महिलाओं के साथ एक अध्ययन में, चंदवंकर (2022) ने यह विश्लेषण करने के लिए ग्रामशियन आधिपत्य की अवधारणा को जोड़ा कि कैसे जाति-आधारित व्यवसाय विभाजन, जो जाति विचारधारा का उपयोग करके प्रमुख जाति समूहों द्वारा बनाए गए थे, ने दलित महिलाओं के लिए विकल्पों को

सीमित कर दिया। निजीकरण के साथ, महिला कचरा बीनने वालों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं तेज हो गई हैं। विट्मर (2021) ने अहमदाबाद में महिला रिसाइक्लर्स (कचरा बीनने वाली) से संबंधित अपने अध्ययन में इस पर प्रकाश डाला है, जहां उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) पहल के तहत भारत में अनौपचारिक रीसाइक्लिंग श्रम को औपचारिक बनाने के प्रयासों के प्रभाव पर प्रकाश डाला है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के निजीकरण प्रयासों के कारण वास्तव में अहमदाबाद में कचरा बीनने वाली महिलाएं इस काम से अलग हो गयीं। निजीकरण के साथ, अनौपचारिक स्क्रैप डीलरों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, ने आजीविका के रास्ते खो दिए हैं क्योंकि अब उनके लिए कचरा इकट्ठा करना और बेचना मुश्किल हो गया है। स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA), एक केंद्रीय व्यापार संघ, ने यह भी पाया कि कचरा बीनने वालों को ट्रांसफर स्टेशनों और लैंडफिल तक पहुंचने के लिए निजी कंपनियों को रिश्वत देनी पड़ती थी। दिल्ली नगर पालिका द्वारा कचरा उठाने की सेवाओं के निजीकरण के कारण पचास प्रतिशत कचरा बीनने वालों ने अपनी नौकरी खो दी

(मिस्त्री एट अल., 2020)।

एक अन्य अध्ययन में, विट्मर (2022) ने अहमदाबाद में कम आय वाली दलित महिला पुनर्चक्रणकर्ताओं और स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन - भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान), ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (2016 नियम) के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा कचरा प्रबंधन कार्य के निजीकरण और मशीनीकरण के उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया। विट्मर ने तर्क दिया कि ये शासन तंत्र शहर में कचरा श्रम को "पुनः स्थानिकीकरण" और "पुरुषीकरण" की ओर ले जा रहे थे। महिलाओं को कचरा पदार्थों तक पहुँचने में कठिनाई हुई, जिससे शारीरिक और वित्तीय बोझ बढ़ गया और दैनिक आय में गिरावट आई। नगरपालिका अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर मौजूदा अनौपचारिक श्रमिकों को मान्यता नहीं दी है, जिन्हें वर्तमान प्रणाली के भीतर अंधेरे में धकेल दिया गया है (कानेकल, 2019)। फुलवानी और चंदेल (2019) के एक अध्ययन ने अहमदाबाद में कचरा बीनने वाली महिलाओं में उच्च रक्तचाप, खांसी, नाक में जलन, पोषण की कमी, अनियमित माहवारी, एनीमिया और ईोसिनोफिलिया जैसे व्यावसायिक स्वास्थ्य मुद्दों की उच्च व्यापकता पर प्रकाश डाला।

हालाँकि, शहरी भारत में घर-घर कचरा संग्रहण में महिला श्रमिकों की भागीदारी पर सीमित अध्ययन उपलब्ध हैं। इस प्रकार, यह अध्ययन अनौपचारिक क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर मौजूद महिलाओं, विशेषकर आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने का प्रयास करता है। कचरा मूल्य श्रृंखला में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उनके काम के बोझ की सीमा, उनके रोजगार की व्यवस्था, मजदूरी, काम की स्थिति, कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रवास के गंतव्य पर सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को मैप किया गया है।

अध्याय 3

भारत में कचरा प्रबंधन के लिए नियामक ढांचा

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) भारत में SWM के लिए जिम्मेदार है और इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) है। कानेकल (2019) के अनुसार, यह एक संस्थागत चुनौती है क्योंकि यह कचरा प्रबंधन को पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे में बदल देता है। 2016 के नियमों ने 2000 से लागू पहले के नियमों को प्रतिस्थापित कर दिया। शहरों और कस्बों सहित भारत के सभी शहरी क्षेत्रों को नियमों के तहत निर्धारित नगरपालिका ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए निर्देशित किया गया था, और 2016 के अपडेट में सभी बस्तियों को शामिल किया गया था, न कि केवल शहरी स्थानीय निकायों (ULB) (एएमसी, 2020)। नियम स्रोत पर पृथक्करण, सैनिटरी कचरे का प्रबंधन, संग्रह के लिए उपयोगकर्ता शुल्क और खाद बनाने को बढ़ावा देने जैसे पहलुओं को अनिवार्य करते हैं (कानेकल, 2019)। हालाँकि, नियम भारत में कचरा प्रबंधन कार्य में लगे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करते हैं और केवल तकनीकी-प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। कचरा प्रबंधन क्षेत्र पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इस प्रक्रिया पर निजी संस्थाओं का नियंत्रण बढ़ गया है और संसाधन के रूप में कचरे तक उनकी पहुंच बढ़ गई है (मजूमदार, 2023)। इसके अलावा, कनेल (2019) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे 2016 के

नियम कचरा-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जैसे केंद्रीकृत समाधानों पर केंद्रित हैं, और एसडब्ल्यूएम के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा नहीं देते हैं। नियम नगर पालिकाओं को अपनी कचरा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप निजी कलाकारों को काम का ठेका दे दिया गया है और काम की अस्थायी प्रकृति के कारण श्रमिकों के लिए आजीविका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है (मिश्री एट अल., 2020)। एक समावेशी प्रणाली स्थापित करने के बजाय जो अनौपचारिक श्रमिकों को उचित मान्यता और सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत करेगी, नियम उन्हें एक अनिश्चित स्थिति में डाल रहे हैं।

2014 में लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता को एक प्रमुख विकास प्राथमिकता बनाने पर केंद्रित था। कचरे पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने से 2016 के नियम तैयार किए गए।

टिकाऊपन को मोटे तौर पर पर्यावरण का प्रश्न माना जाता है, जिसमें मानवीय तत्व की बहुत कम या कोई परवाह नहीं की गयी है। हैरिस-व्हाइट (2015) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कचरा प्रबंधन कार्य के लिए नगर निगमों द्वारा नियोजित श्रम बल में पुरुषों की संख्या बढ़ी है, और जो महिलाएं मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला उठाने के काम करती हैं, उनके अवसरों में गिरावट देखी गई है। अधिकांश नौकरियाँ मौखिक अनुबंधों पर आधारित होती हैं और इन्हें बंधुआ मज़दूरी भी कहा जा सकता है। हाल ही में, विभिन्न निजीकरण

चित्र 1 - कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र को दर्शाता है (स्रोत: विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की वेबसाइट)

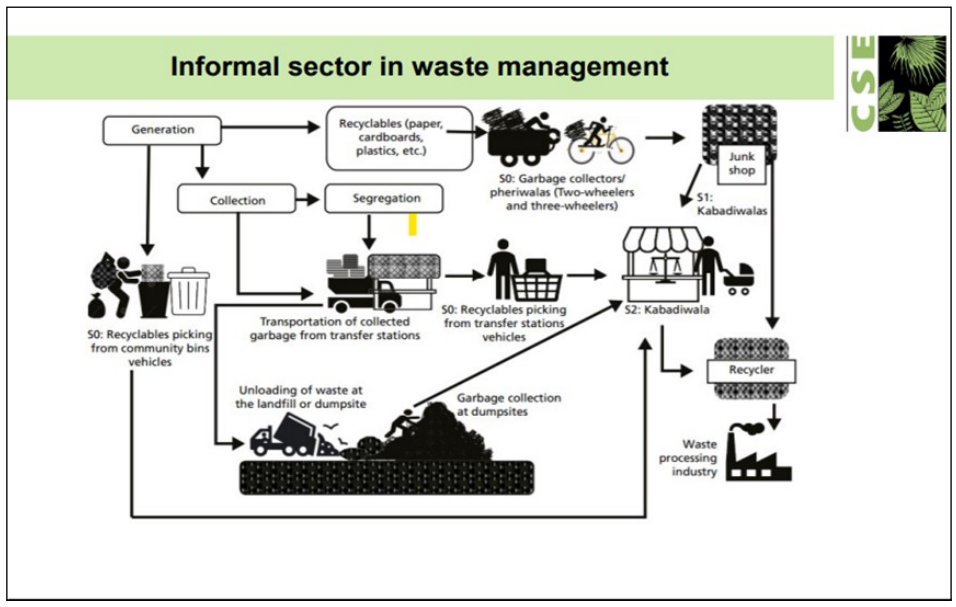

पहलों की शुरूआत के साथ, पहले से ये काम कर रहे विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को इस अनौपचारिक प्रणाली से अलगाव का सामना करना पड़ा है। इस अलगाव से उचित वेतन और संपत्ति स्वामित्व की संभानाएं कम होती हैं (मजूमदार, 2023)। कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक या स्व-रोज़गार श्रमिकों के रूप में उनके योगदान को पहचानने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, इन नीतियों के कारण उन्होंने उन्हें बिना किसी वैकल्पिक संभावनाओं के अपनी आजीविका और रोजगार के रास्ते खो दिए हैं।

कचरे की मूल्य श्रृंखला

अहमदाबाद के बाहरी इलाके में नारोल में पिराना लैंडफिल की एक यात्रा, जहां हवा धुएं और तेज बदबू से भरी है, शहर में कचरा प्रबंधन की कहानी बताती है। बढ़ता हुआ कचरा 1980 के दशक से जमा हो रहा है। यह अहमदाबाद में ठोस कचरे का अंतिम गंतव्य है। इस लैंडफिल के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों द्वारा महसूस किया जाता है (महंती और सुगाथन, 2018)। शहर के हाशिये पर इस लैंडफिल की मौजूदगी उन श्रमिकों की वास्तविकता को भी दर्शाती है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जातिगत शुद्धता की धारणाओं के कारण समाज के हाशिये पर धकेल दिया गया है। नतीजतन, इस कचरे की आपूर्ति श्रृंखला और श्रृंखला के प्रत्येक नोड पर लगे श्रमिकों को उजागर करना अनिवार्य हो जाता है। कचरे की आपूर्ति श्रृंखला उत्पादन से शुरू होती है, जिसके बाद घर-घर जाकर संग्रह करना, सार्वजनिक कूड़ेदानों से संग्रह करना या स्पॉट संग्रह करना आता है। 2020 तक, भारत में 4,237 नगरी निकायों में से 1,863 निकायों में घर-घर कचरा संग्रहण किया जाता था। कथित तौर पर 436 निकायों में स्रोत पर कचरे को अलग करने का पालन किया गया था। वहां भी, केवल गीले और सूखे कचरे को प्रभावी ढंग से अलग किया जाता है, और बायोमेडिकल कचरे जैसे सैनिटरी नैपकिन, डायपर, बाल इत्यादि को सख्ती से अलग नहीं किया जाता है। (स्वच्छ सर्वेक्षण, 2020 जैसा कि शर्मा, 2023 में उद्धृत किया गया है)। एकत्र किए गए कचरे को अलग किया जाता है और फिर रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशनों (आरटीएस) में ले जाया जाता है, और वहां से प्रसंस्करण या उपचार के लिए भेजा जाता है। ठोस कचरा के पुनर्चक्रण के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं मौजूद हैं। बचे हुए कचरे को अंततः लैंडफिल में निपटाया जाता है।

चित्र 2 - कचरे की मूल्य श्रृंखला को दर्शाता है (स्रोत: कुमार और अग्रवाल, 2020)

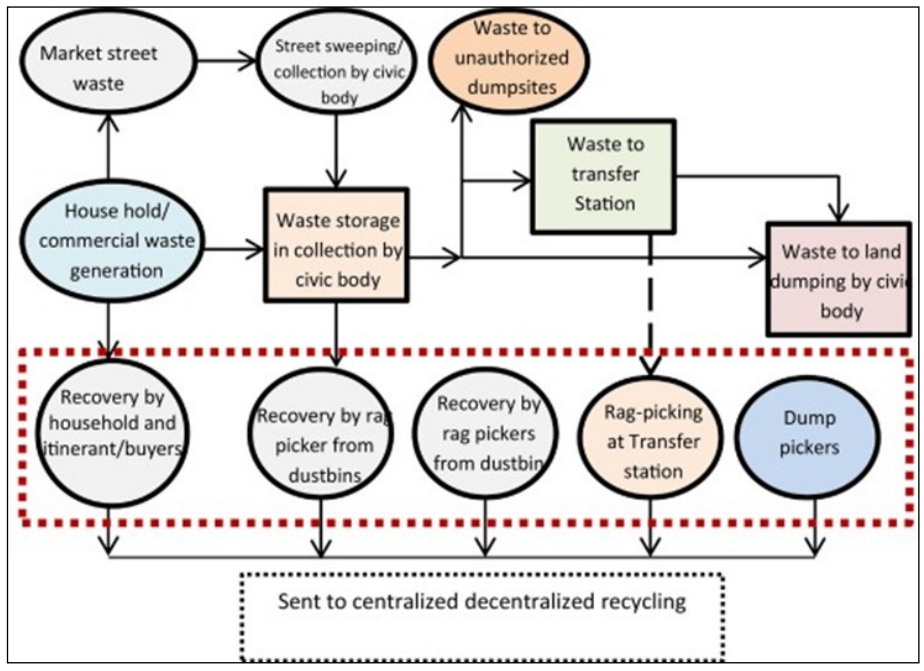

अहमदाबाद में, घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारियों द्वारा एकत्र किया गया कचरा प्रत्येक वार्ड में ट्रांसफर स्टेशनों पर और वहां से उपचार संयंत्रों में जमा किया जाता है। लगभग 400 मीट्रिक टन क्षमता के आठ ट्रांसफर स्टेशन हैं, जिनका निर्माण सात जोन में किया गया है। एएमसी द्वारा एकत्र किए गए कचरे का 90

प्रतिशत हिस्सा अवैज्ञानिक रूप से नारोल में पिराना लैंडफिल में फेंक दिया जाता है जो 207.56 एकड़ में फैला हुआ है और जिसकी 200 मीटर से अधिक ऊंचाई है। लैंडफिल 1980 के दशक से बन रहा है। यहाँ वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2,300 मीट्रिक टन कचरा प्राप्त होता है, जिसे खुले में जलाया जाता है (महंती और सुगाथन, 2018; ओट्स एट अल।, 2018)।

चित्र 3 - अहमदाबाद में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण को दर्शाया गया है (स्रोत: एएमसी)

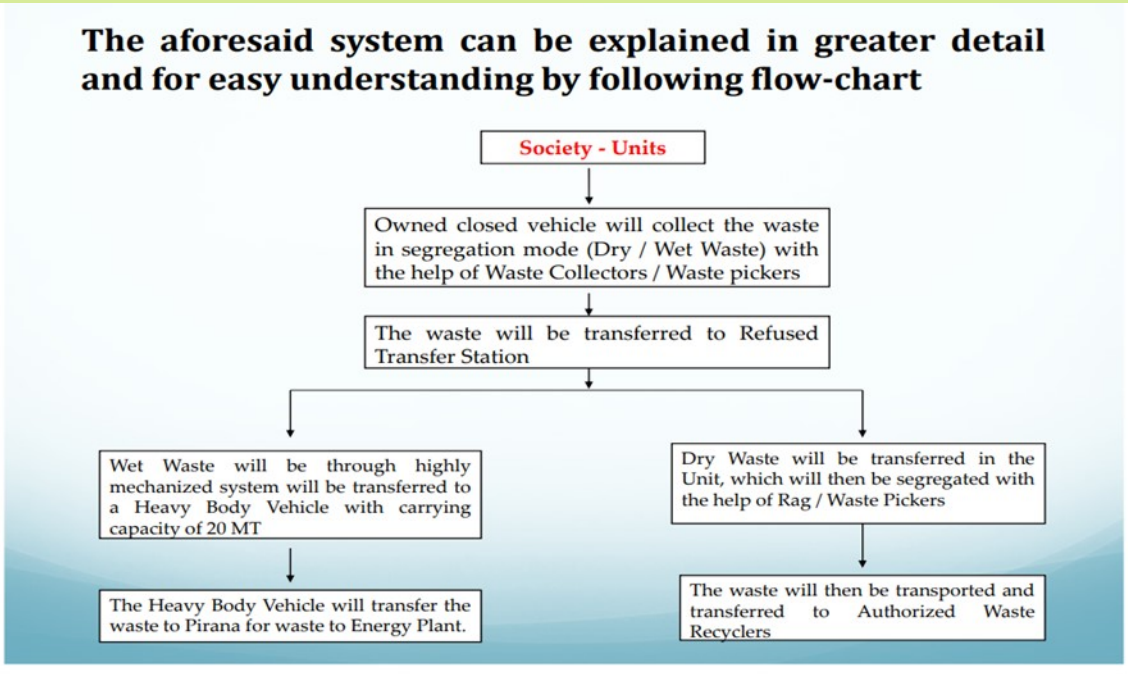

अध्याय 4

सर्वेक्षण स्थानों पर ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली

अहमदाबाद

अहमदाबाद की 65 लाख आबादी दैनिक आधार पर लगभग 4,100 टन और मासिक आधार पर 1,10,667 टन कचरा उत्पन्न करती है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत का प्रबंधन एएमसी द्वारा किया जाता है जो शहर में नगरपालिका ठोस कचरे को संभालने के लिए जिम्मेदार है। एएमसी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार को सात क्षेत्रों और 48 वार्डों में विभाजित किया गया है, जिसमें लगभग 466 वर्ग किलोमीटर और लगभग 63 लाख की आबादी शामिल है। SWM स्टाफ में 13,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। 1,500 से अधिक वाहन या उपकरण हैं। इसके अलावा, SWM विभाग का वार्षिक बजट लगभग 800 करोड़ है।

2008 में, एएमसी द्वारा निजी संस्थाओं को ठेका देकर शहर में कचरा प्रबंधन का निजीकरण कर दिया गया था। इस समय, कुछ कचरा बीनने वालों ने भी अपनी नौकरी खो दी (पाडोडे, 2022)। अहमदाबाद में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वर्ष 2009 में शुरू हुआ और इसे निजी ठेकेदारों को आउटसोर्स किया गया है। बदले में ठेकेदार एक उपठेका प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों को नियुक्त करते हैं जो आवासीय इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कचरा इकट्ठा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कचरा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। SEWA ने 2004 में कचरा बीनने में लगी महिलाओं की एक सहकारी समिति को बढ़ावा दिया, जिसने 46,000 घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए AMC से अनुबंध प्राप्त किया। लेकिन निजीकरण के

साथ काम को बड़े निगमों को सौंप दिया गया क्योंकि छोटी या मध्यम आकार की सहकारी समितियाँ या पारंपरिक कचरा बीनने वाले निविदा में शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे (SEWA, 2010)। वर्तमान में, निविदा के तहत अलग-अलग कचरे के संग्रह के लिए एक टिपिंग समझौता किया गया है। मजदूर सुबह आवासीय इकाइयों से और शाम को वाणिज्यिक इकाइयों से कचरा इकट्ठा करते हैं। एएमसी के अनुसार सभी दिनों में 100 प्रतिशत इकाइयों को कवर करने का दावा किया गया है। घर-घर कचरा संग्रहण के लिए, बंद बॉडी हाइड्रोलिक यूरो III वाहनों को शहर की सीमाओं के भीतर तैनात किया गया है, जिसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डिब्बे हैं। नियमों के अनुसार, 16 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों और पांच लाख वाणिज्यिक इकाइयों से अलग-अलग कचरे को एकत्र करना आवश्यक है, जिसके लिए एएमसी संपत्ति कर बिल में क्रमशः एक रुपये और दो रुपये का दैनिक शुल्क शामिल करता है। निजी ठेकेदार ड्राइवर, ईंधन, रखरखाव, प्रति वार्ड एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने और वाहन पर एक शिकायत संख्या पेंट करने के लिए जिम्मेदार हैं। मार्च 2019 को अहमदाबाद में एसडब्ल्यूएम कलेक्शन वाहनों पर एक रिपोर्ट के अनुसार, सूखे और गीले कचरे के संग्रह के लिए

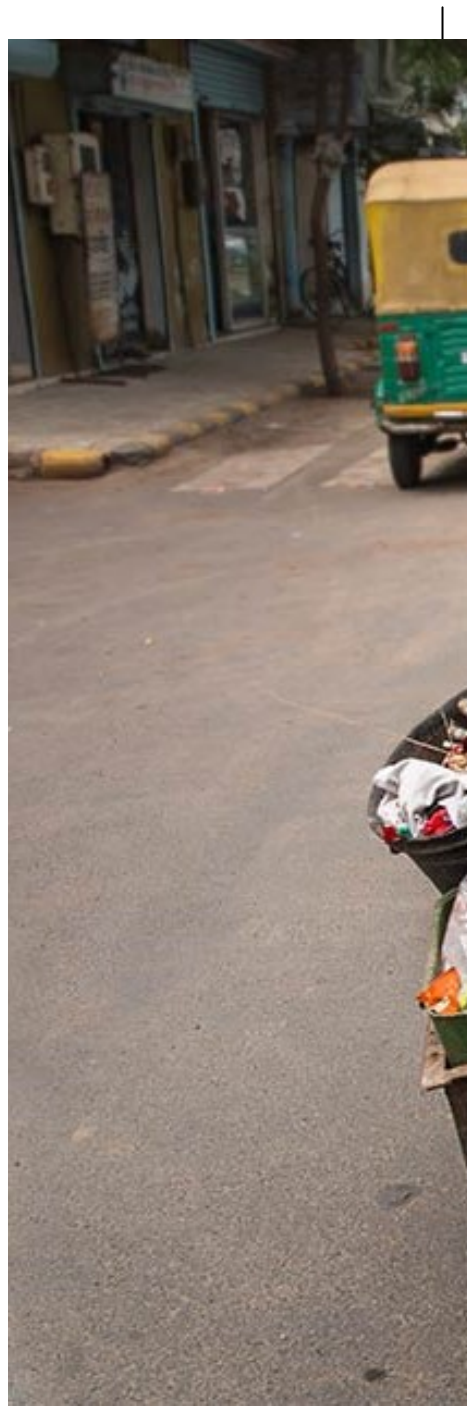

अलग-अलग डिब्बे वाले कुल 1,582 एक और तीन टन टाटा एसीई और 407 प्रकार के बंद बॉडी वाहन 2015 में अहमदाबाद के 48 वार्डों से कचरा दैनिक संग्रह के लिए खरीदे गए थे। शहर के पूर्वी क्षेत्र में, ओम स्वच्छता निगम और जिगर ट्रांसपोर्ट कंपनी को घर-घर कचरा संग्रहण का ठेका लेने वाले विक्रेता के रूप में दर्शाया गया था।

एकत्र किए गए कचरे को श्रमिकों द्वारा आरटीएस (कुल आठ आरटीएस कार्यरत हैं) और उसके बाद उपचार संयंत्रों में स्थानांतरित किया जाता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी सुबह सात बजे संग्रह प्रक्रिया शुरू करते हैं। एएमसी के अधिकार क्षेत्र में, इस विधि के माध्यम से लगभग 1,700 मीट्रिक टन ठोस कचरा एकत्र किया जाता है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। एएमसी का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया मशीनीकृत है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कचरे को भौतिक रूप से केवल एक बार ही संभाला जाए। इस प्रकार, उन श्रमिकों की स्थितियों और अनुभवों पर विचार करना अनिवार्य है जो प्रतिदिन कचरे के संपर्क में आते हैं। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) के भी स्वचालित होने का दावा किया गया है, प्रत्येक आरटीएस पर एक एमआरएफ है। आरटीएस का निर्माण एएमसी द्वारा किया जाता है और उन एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें निगम से संचालन और रखरखाव अनुबंध प्राप्त हुआ है। आरटीएस में, सूखे कचरे को अलग करने और इसे प्रसंस्करण के लिए एमआरएफ में स्थानांतरित करने के लिए 600 महिलाओं को काम पर रखा गया है, और लगभग 2,000 कूड़ा बीनने वालों को इस प्रणाली में एकीकृत करने का संकेत दिया गया है। बचे हुए कचरे को 84 एकड़ में फैले पिराना डंप साइट और बोपल-घुमा में एक अन्य डंप साइट पर डंप किया जाता है (एएमसी, 2020)।

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर (आरएफआईडी) के माध्यम से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। जीपीएस मॉनिटरिंग इनफिनियम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित 'इकोस्किपर एप्लिकेशन' के माध्यम से की जाती है। अहमदाबाद में कुल कचरे का लगभग 50 प्रतिशत घर-घर जाकर संग्रह करने और सड़क साफ़ करने के अभ्यास से एकत्र किया जाता है (एएमसी, 2020)।

गांधीनगर

गांधीनगर नगर निगम (जीएमसी) के स्वच्छता और पर्यावरण विभाग राजधानी शहर में एसडब्ल्यूएम के लिए जिम्मेदार हैं। जीएमसी की वेबसाइट के अनुसार, प्रति दिन लगभग 95 मीट्रिक टन ठोस कचरा, जिसमें 10 मीट्रिक टन निर्माण और मलबे का कचरा शामिल है, उत्पन्न होता है, जिसे एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार एकत्र, परिवहन, उपचार और निपटान किया जाता है। गांधीनगर में कचरा संग्रहण का काम 2013 में शुरू हुआ, जिसके तहत

आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्रों से कचरा एकत्र किया जाता है। अहमदाबाद और सूरत की तरह, संग्रह का काम सूखे, गीले और खतरनाक कचरे के लिए अलग-अलग डिब्बे वाले बंद वाहनों में किया जाता है। लगभग 50 आरएफआईडी और जीपीएस सक्षम वाहनों को तैनात करने का संकेत दिया गया था, जो दैनिक आधार पर 100 प्रतिशत आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयों को कवर करते थे। एकत्रित कचरे को आरटीएस में ले जाया जाता है। इसके अलावा, कचरे को छांटने और अलग करने के लिए तीन एमआरएफ हैं। सरकार के स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जुलाई 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, गांधीनगर ने दो क्षेत्रों और सात वार्डों से घर-घर कचरा संग्रहण की सूचना दी, जिसमें 43,295 घर और प्रतिष्ठान शामिल थे। जीएमसी ने बताया कि 100 प्रतिशत इकाइयों में स्रोत पर पृथक्करण किया गया था। जोन 2 में स्वच्छता कारपोरेशन घर-घर कचरा संग्रहण कार्य के लिए जीएमसी द्वारा नियुक्त संग्रहणकर्ता है।

सूरत

सूरत नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, नौ क्षेत्रों और 30 वार्डों में फैली 46 लाख की आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) के साथ, सूरत शहर ने अक्टूबर 2023 में प्रति दिन औसतन 2,600 मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न किया। इसमें से 2,114 मीट्रिक टन या 78

Name of Transfer station	Zone
Bhatar	South west
Katargam	North & Central (Part)
Varachha	East
Anjana	South-East
Pal	West
Bhestan	South
Kosad	North-East-West
Dindoli	South-East

प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के माध्यम से एकत्र किया गया था। एसएमसी का एसडब्ल्यूएम विभाग, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शहर में ठोस कचरे को संभालने के लिए जिम्मेदार है। कचरा प्रबंधन तीन चरणों में होता है। प्राथमिक संग्रह और परिवहन में स्वीपिंग, स्क्रैपिंग और ब्रशिंग गतिविधि, होटल-रसोई कचरा आदि के माध्यम से एकत्र किया गया ठोस कचरा शामिल है। इस चरण में डोर-टू-डोर कचरा संग्रह शामिल है। शहर में डोर-टू-डोर कलेक्शन की शुरुआत 2004 में हुई थी। सभी जोनों में ठोस कचरा के घर-घर जाकर संग्रहण के लिए विभिन्न एजेंसियों को लगाया गया है। द्वितीयक परिवहन में प्राथमिक परिवहन के माध्यम से एकत्र किए गए ठोस कचरा को स्थानांतरण स्टेशनों तक ले जाना शामिल है, जहां से इसे अंततः खजोद लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है। एसएमसी की वेबसाइट के अनुसार, शहर में आठ ट्रांसफर स्टेशन हैं और सभी चालू हैं।

एसएमसी की वेबसाइट एक पोर्टल चलाती है जो नागरिकों को डोर-टू-डोर कलेक्शन में लगे वाहनों सहित कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों की लाइव ट्रैकिंग की अनुमति देती है। पोर्टल के अनुसार, नवंबर, 2023 तक 643 वाहन घर-घर से कचरा संग्रहण में लगे हुए हैं।

अध्याय 5

क्रियाविधि

यह अध्ययन गुजरात के तीन शहरों - अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में किए गए क्षेत्रीय शोध पर आधारित है। चूँकि अध्ययन का उद्देश्य घर-घर कचरा संग्रहण में लगी आदिवासी महिला श्रमिकों की स्थितियों को समझना था, इसलिए जिन श्रमिकों को इसमें लगाया गया था, वे बड़े पैमाने पर इसी समूह से हैं। फील्डवर्क में अगस्त 2023 और अक्टूबर 2023 के बीच, गांधीनगर और अहमदाबाद में 101 और सूरत में 95 श्रमिकों के परिवारों के साथ संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके एक घरेलू सर्वेक्षण शामिल था। अध्ययन के लिए स्नोबॉल सैंपलिंग विधि चुनी गई थी ताकि श्रमिकों की बस्तियों की पहचान की जा सके। इसके बाद बैठकें आयोजित की गईं अध्ययन में भाग लेने के लिए सहमति देने वालों का सर्वेक्षण किया गया। डेटा संग्रह को चार फोकस समूह चर्चाओं द्वारा पूरा किया गया जो शहरों में चार अलग-अलग बस्तियों में रहने वाले श्रमिकों के साथ आयोजित की गई थीं। गोपनीयता बनाए रखने के लिए बस्तियों का स्थान उजागर नहीं किया गया है। इसके साथ ही, रिपोर्ट कार्यक्षेत्र के अवलोकन और कचरा संग्रहकर्ता समुदाय के साथ चर्चा पर आधारित है। सर्वेक्षण में शामिल लगभग सभी श्रमिक गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी प्रवासी हैं, जो आम तौर पर जोड़े में काम करते हैं, पति घर-घर कचरा संग्रहण वाहन चलाता है, और महिला कचरा इकट्ठा करती है और उसे अलग करती है।

क्षेत्र अनुसंधान शुरू करने से पहले, कचरा प्रबंधन में शामिल प्रक्रियाओं, अध्ययन के तहत शामिल शहरों की स्थिति और लिंग, जाति, आदिवासी और प्रवासी पहचान भारत में कचरा प्रबंधन क्षेत्र के भीतर श्रम संबंध को आकार देने में भूमिका को समझने के लिए व्यापक साहित्य समीक्षा और डेटा विश्लेषण किया गया था।

यह अध्ययन अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में घर-घर कचरा प्रबंधन कार्य में लगे श्रमिकों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल के साथ-साथ उनके वेतन, काम करने और रहने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा लाभों की समझ प्रदान करता है। अध्ययन का ध्यान उन आदिवासी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर है जो अपने पतियों के साथ प्रवास करती हैं और कचरे को इकट्ठा करने और अलग करने के काम का एक महत्वपूर्ण घटक करती हैं। महिला श्रमिक कचरा संग्रहण कार्य और घरेलू काम के दोहरे बोझ का सामना करती हैं। उनके लिंग और जनजातीय पहचान के अंतर्संबंध का भी पता लगाया गया है। कचरा प्रबंधन कार्यबल की असंगठित प्रकृति के साथ जुड़ी प्रवासन, लिंग और आदिवासी पहचान की राजनीति इस अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भारत में एसडब्ल्यूएम नियमों और अन्य नीतिगत पहलों के प्रक्षेप पथ में प्रगतिशील परिवर्तनों के पीछे कार्रवाई-आधारित अनुसंधान को एक कारण बताया गया है (शर्मा, 2023)। इस प्रकार, इसका उद्देश्य एसडब्ल्यूएम क्षेत्र में लगे प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मजबूत उपायों की वकालत करने के लिए इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग करना है।

अध्याय 6

मुख्य निष्कर्ष और विश्लेषण

प्रवासन पैटर्न और अनुबंधातम्क व्यवस्था

Map 1 - Migration corridor from Dahod and Jabhua to Ahmedabad, Gandhinagar, and Surat

गुजरात में एसडब्ल्यूएम में लगे श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा झाबुआ, मध्य प्रदेश के प्रवासियों का है (श्रीवत्सन, 2020)। झाबुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश (एमपी) में एक आदिवासी जिला है, जहां मौसमी प्रवासन बहुत अधिक है क्योंकि आदिवासी भूमि जोत छोटी है और जीवित रहने के लिए पर्याप्त फसल पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कपास, मक्का और बाजरा छोटी जोत पर उगाए जाते हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में वन क्षेत्र भी घट रहा है,

जिससे आदिवासी आबादी की आजीविका प्रभावित हो रही है, जो निजी ऋणदाताओं से जुड़े कर्ज के जाल में फंस गई है। आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित भारतीय संविधान की छठी अनुसूची राज्य में लागू नहीं है (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 2023)। झाबुआ के श्रमिक पहले मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों के रूप में काम करने के लिए अंतर-राज्य प्रवास करते थे। कृषि क्षेत्र के भीतर मशीनीकरण के बाद, उन्हें गुजरात के शहरों में निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा (यादव, 2020)। दूसरा क्षेत्र जहां से श्रमिक मुख्य रूप से अहमदाबाद, सूरत और गांधीनगर की ओर पलायन करते हैं, वह दाहोद, गुजरात है। झाबुआ की तरह, इस क्षेत्र में भी भील जनजाति का वर्चस्व है और आजीविका की स्थितियाँ झाबुआ (रामचंद्रन, 2023) के समान हैं। तीनों शहरों में 196 उत्तरदाताओं की सर्वे की गयी नमूना आबादी में से 142 परिवार यानी 72 प्रतिशत झाबुआ जिले से थे, और 42 परिवार यानी 21 प्रतिशत दाहोद जिले से थे। औसतन, श्रमिक लगभग 10 महीने काम के गंतव्य पर रहते हैं, और शेष दो महीने अपने स्रोत गांव में बिताते हैं।

घर-घर कचरा संग्रहण कार्य में श्रमिकों की भर्ती के तरीके में मौजूदा नेटवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालते

चार्ट 1 - उत्तरदाताओं की स्रोत स्थिति का प्रतिनिधित्व

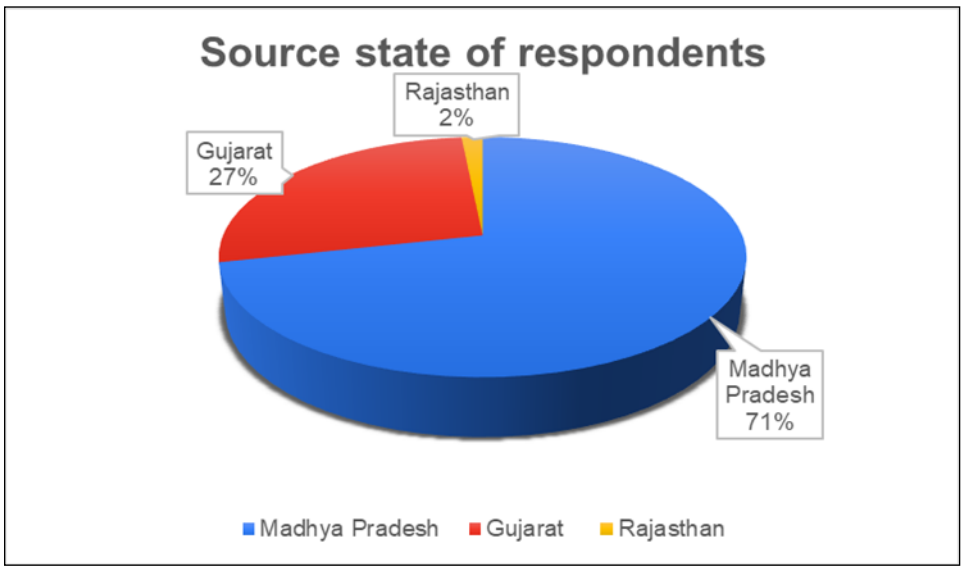

चार्ट 2 - उत्तरदाताओं के स्रोत जिले का प्रतिनिधित्व

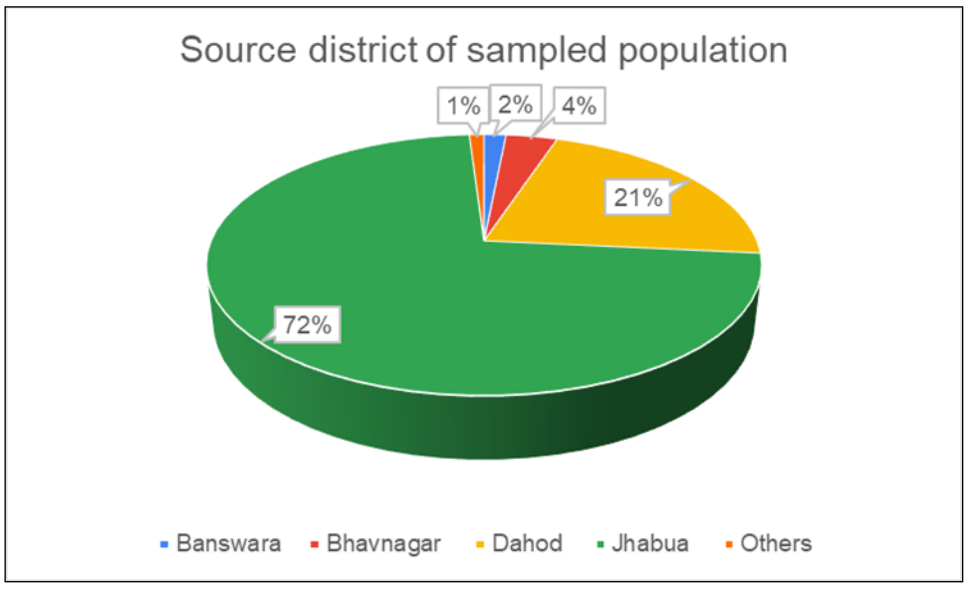

हुए, एक बस्ती के श्रमिकों ने बताया कि वे एक मुकद्दम के माध्यम से दाहोद से गांधीनगर पहुंचे, जिसके संपर्क में वे अपने गांव में आए थे। उन्हें इस काम के बारे में गाँव के रिश्तेदारों और दोस्तों से मिली जानकारी के माध्यम से पता चला, जो इस काम के लिए पलायन कर गए थे। मुकद्दम ने श्रमिकों को इकट्ठा किया और उन्हें इस काम में आगे बढ़ने में मदद की। श्रमिकों ने साझा किया कि उनमें से अधिकांश शुरू में निर्माण कार्य में लगे थे और धीरे-धीरे घर-घर कचरा संग्रहण में लग गए। कुछ श्रमिकों ने बताया कि वे पहली बार इस काम में शामिल होने के लिए लगभग चार से पांच महीने पहले गांव से एक साथ आए थे। अहमदाबाद की एक बस्ती के श्रमिकों ने प्रवास के इसी तरह के पैटर्न का संकेत दिया। इस काम में शामिल एक परिचित ने उन्हें इस काम के बारे में बताया और गांव के अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दी। श्रमिकों ने साझा किया कि उन्हें अपने गांवों में

चार्ट 3 - उत्तरदाताओं की आयु सीमा को दर्शाता है

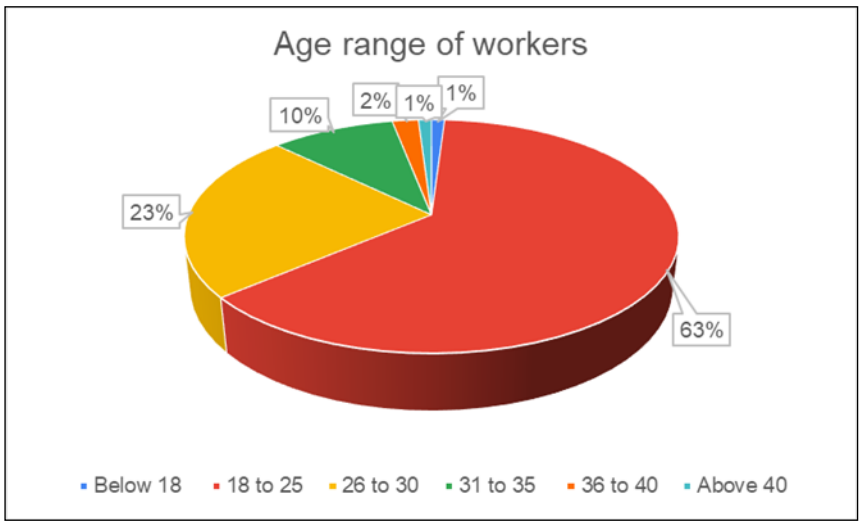

चार्ट 4 - उत्तरदाताओं के शिक्षा स्तर का प्रतिनिधित्व

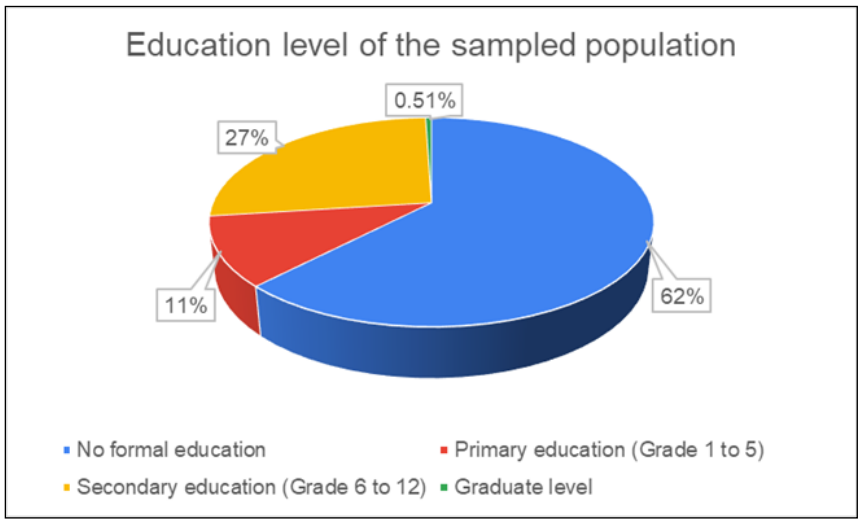

आजीविका की असुरक्षाओं और वित्तीय चुनौतियों के कारण शहर की ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए अपने आदिवासी गांवों को छोड़ना पड़ा। यह भी ध्यान रखना उचित है कि नमूना आबादी का 63 प्रतिशत 18 से 25 वर्ष की उम्र का है, और नमूना आबादी के लगभग 62 प्रतिशत ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है।

गांधीनगर बस्ती के श्रमिकों ने बताया कि वर्तमान में, स्वच्छता कारपोरेशन कंपनी के पास जीएमसी से घर -घर कचरा संग्रहण का ठेका है, और कर्मचारी कंपनी के पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करते हैं। इससे पहले, एक और कंपनी थी जिसके पास अनुबंध था और उसने अपने संपर्कों के माध्यम से श्रमिकों को नियुक्त किया था। इसी प्रकार, ये श्रमिक भी पहले किसी अन्य इकाई द्वारा किसी अन्य स्थान पर कार्यरत थे। श्रमिकों ने कहा कि जब वे पर्यवेक्षक के संपर्क में रहते हैं, तो कंपनी का कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि प्रशिक्षण के लिए या उनके काम की निगरानी के लिए बस्ती में नहीं आता

है। श्रमिकों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी कि अनुबंध करने वाली इकाई और कर्मचारी के बीच संस्थाओं की कोई परत थी या नहीं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उप-ठेकेदार के ऊपर एक बड़ा ठेकेदार था जिसने उन्हें काम पर रखा था, इस प्रकार श्रमिकों और प्रमुख नियोक्ता, यानी राज्य के बीच ठेकेदारों की एक श्रृंखला का संकेत मिलता है। लेकिन उन्हें न तो उनके नामों के बारे में पता था और न ही उनसे कोई बातचीत हुई थी.

अहमदाबाद की एक बस्ती में, श्रमिकों ने बताया कि जिन निजी कंपनियों के पास घर-घर कचरा संग्रहण का ठेका था, वे जिगर ट्रांसपोर्ट कंपनी और ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन थीं। जिस उप-ठेकेदार ने उन्हें काम पर रखा था, उसने उन्हें अपनी झोपड़ियाँ या झुग्गियाँ बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई थी और वह फोन पर उनके संपर्क में है और कभी-कभी उनसे मिलने भी आता है। वह अहमदाबाद के नरोदा में रहते हैं, और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में भी लगे हुए हैं, लेकिन एक "बड़ा वाहन" चलाते हैं। पूछे जाने पर, श्रमिकों ने बताया कि इस काम में संलग्न होने से पहले उन्होंने किसी भी लिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, और उन्हें पहले से किसी भी नियम या शर्तों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। प्रारंभ में, उन्हें शहर में अपना रास्ता तय करते समय समस्याओं का सामना

करना पड़ा, क्योंकि रास्ते याद रखने में बहुत लंबे थे। हालाँकि, समय के साथ वे अपने काम की प्रकृति को देखते हुए इलाकों का पता लगाने में कामयाब रहे हैं जिसमें वाहन में सवारी करना और उन्हें सौंपे गए क्षेत्र से कचरा इकट्ठा करना शामिल है। अधिकांश नियम और प्रक्रियाएँ काम पर सीखी या समझी गईं।

लगभग 25 परिवारों वाली एक बस्ती के श्रमिकों के अनुसार, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ के एक गाँव से आए थे, उनका ठेकेदार उनके पड़ोसी गाँव से है और अभी भी वहीं रहता है। वह केवल गांव से गंतव्य तक उनकी आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है और अक्सर गंतव्य पर नहीं जाता है। जबकि श्रमिकों का श्रम गंतव्य पर होता है, ठेकेदार केवल अनुबंध की व्यवस्था करके कमाई करता है। श्रमिकों ने कहा कि यदि उनका पैसा फंस जाता है या गंतव्य पर उन्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वे इस ठेकेदार से संपर्क करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि और किससे संपर्क करना है। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदार का रिश्तेदार भी घर-घर से कूड़ा उठाने का काम करता है और उनके साथ उनकी बस्ती में रहता है। उनका मानना था कि वह ठेकेदार के साथ आवश्यक किसी भी बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सक्षम होंगे। ठेकेदार के रिश्तेदार, राजूभाई (बदला हुआ नाम) ने बताया कि वह पहले वापी में शिपिंग क्षेत्र में काम करता था। उनके बड़े भाई उत्तर प्रदेश के आगरा में घर-घर कचरा संग्रहण के काम में लगे हुए थे। राजूभाई जब काफी छोटे थे तब अहमदाबाद आये और इस काम के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के संपर्क में आये। बाद में वह इस ठेकेदार से जुड़ गया और गांधीनगर आ गया. उन्होंने साझा किया कि ऐसी व्यवस्था गांधीनगर की एक अन्य बस्ती में मौजूद है, जहां लगभग 25 श्रमिक ठेकेदार के एक अन्य रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, जो श्रमिकों के साथ काम भी करता है और रहता है। हालाँकि, वह इस बात पर प्रकाश नहीं डाल पाए कि ऐसे कितने ठेकेदार मौजूद हैं और उपठेके की क्या -क्या परतें मौजूद हैं।

सूरत की एक बस्ती में, श्रमिकों ने कहा कि कुछ महीने पहले कुछ श्रमिक पलायन कर गए थे जब उनके गांव के बालाभाई (बदला हुआ नाम) ने उनसे संपर्क किया था, जो उस समय ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन के साथ ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। कुछ श्रमिक पहले से ही ओम स्वच्छता

कॉर्पोरेशन में उनके साथ काम कर रहे थे। सूरत आने के बाद, बालाभाई (जो अब पर्यवेक्षक हैं) के साथ श्रमिकों ने जिगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया और कुछ दिन पहले निजी भूमि पर अस्थायी आश्रय स्थापित किया। उनके काम में खुले कूड़ा डंपिंग स्थानों से कूड़ा उठाना शामिल है। बालाभाई 9-10 वाहनों के प्रबंधन के प्रभारी हैं और यदि कोई ड्राइवर छुट्टी पर है तो वह एक वाहन भी चलाते हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह इस काम में इसलिए आये क्योंकि उनके भाई ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन में पर्यवेक्षक थे, उन्होंने श्रमिकों की भर्ती में ग्रामीण नेटवर्क की भूमिका पर प्रकाश डाला। बालाभाई ने कहा कि पर्यवेक्षकों का वेतन उनकी देखरेख में वाहनों की संख्या पर आधारित है। "जितने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा गाड़ी देंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा", इस प्रकार श्रमिकों की भर्ती पर्यवेक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है जो फिर गांवों में अपने मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती करते हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि दिवाली के बाद गांवों से अतिरिक्त मजदूर शामिल होने वाले हैं और वह तब बढ़ी हुई संख्या में वाहनों का प्रबंधन करेंगे। सूरत की एक अन्य बस्ती में रहने वाले श्रमिकों ने भी दोहराया कि उन्हें इस काम के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से पता चला जो पहले से ही काम कर रहे थे। कुछ कर्मचारी पहले से ही जामनगर और राजकोट जैसी जगहों पर कचरा प्रबंधन में काम कर रहे थे, लेकिन बेहतर मजदूरी की तलाश में सूरत चले गए।

कचरा प्रबंधन की ओर बदलाव

पिछले एक से पांच वर्षों में नमूना आबादी में से लगभग 55 प्रतिशत ने इस काम में प्रवेश किया, जो दर्शाता है कि यह गुजरात की ओर पलायन करने वाले आदिवासियों के लिए कार्य का एक नया क्षेत्र है। अहमदाबाद की एक बस्ती के श्रमिकों ने बताया कि उन्होंने लगभग दो से तीन साल पहले कचरा प्रबंधन

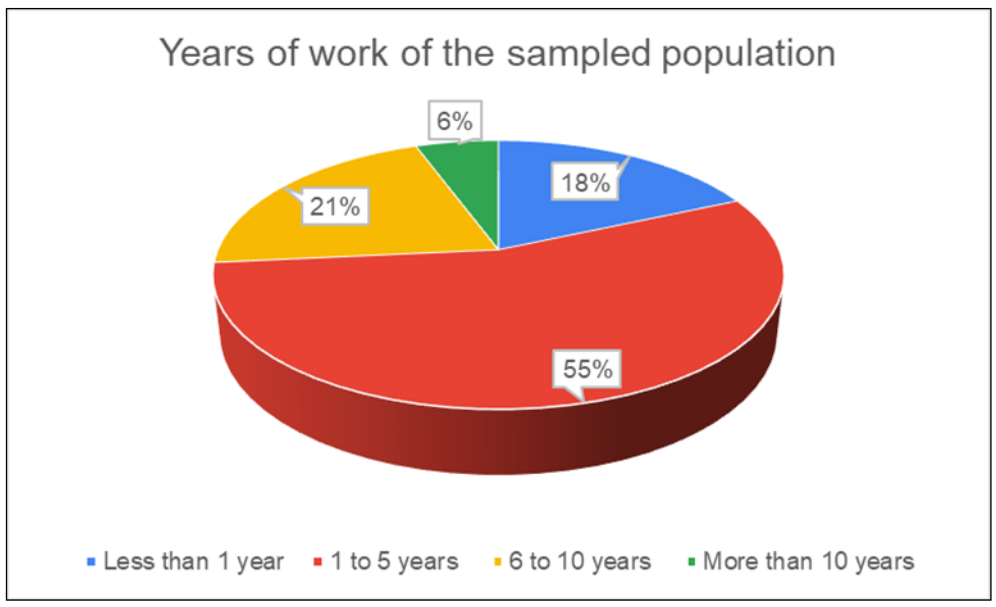

चार्ट 5 - उत्तरदाताओं के कार्य के वर्षों का प्रतिनिधित्व

क्षेत्र में प्रवेश किया था, और उससे पहले, वे गाँव में अपनी छोटी जोत पर काम कर रहे थे। एक मज़दूर ने साझा किया कि उस समय वह ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए मौसमी रूप से गुजरात के एक शहर भरूच में प्रवास करता था और फिर गाँव वापस चला जाता था। गाँव के अन्य लोग भी कुछ महीनों के लिए निर्माण श्रमिक या ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए कस्बों और शहरों में चले जाते थे और फिर वापस चले जाते थे। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य में शामिल होने का कारण अनुबंध के तहत मिलने वाले नियमित वेतन और स्क्रैप की बिक्री के माध्यम से दैनिक आय अर्जित करने की संभावना बताया गया था। सन्नभदति (2019) के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि शहरों में गेटबंद वाले परिसरों में कचरे

को जमा करने या सीधे कबाड़ीवालों को बेचने की जगह नहीं होती है। इससे इन परिसरों में उत्पन्न होने वाले कचरे की बड़ी मात्रा को देखते हुए, घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने वालों को स्क्रैप के रूप में बेचने के लिए अधिक कचरा प्राप्त करने की सम्भावना रहती है।

श्रमिकों ने यह भी बताया कि यह काम निर्माण कार्य जितना शारीरिक रूप से कठिन नहीं है, जिसके लिए उन्हें ईंटों और अन्य निर्माण सामग्री के भारी भार के साथ ऊंचाइयों पर चढना पड़ता है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के चोट लगने की संभावना भी अधिक थी। इसके अलावा, नाकों पर काम की तलाश करते समय, श्रमिकों को यह पता नहीं होता था कि उन्हें काम के लिए कहाँ से 'उठाया' जाएगा और कई बार कार्यस्थल और उनकी बस्ती की दूरी बहुत होती थी, और महिलाओं को एक अलग स्थान पर भेजा जाता था। इसकी तुलना में, घर-घर कचरा संग्रहण के साथ, उनके पास प्रतिदिन कवर करने के लिए एक विशिष्ट मार्ग होता है, कम अनिश्चितता होती है, और दंपति एक साथ काम कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा के डर के बिना बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं। गांधीनगर में बस्ती के श्रमिकों के अनुसार, इस काम

में, वे चिकित्सा व्यय या काम की तलाश में अवधि जैसी आकस्मिकताओं के लिए अपना मासिक वेतन बचाने में सक्षम थे। वे भंगार बेचकर अपना रोजमर्रा का खर्च चलाते हैं। नगर निगम से अनुबंधित इकाई द्वारा आयोजित निविदा के तहत श्रमिकों को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

सूरत की एक बस्ती के कुछ श्रमिकों के अनुसार, संक्रमण 2020 में कोविड महामारी द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान हुआ। श्रमिक अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में निर्माण कार्य में लगे हुए थे। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, सभी निर्माण गतिविधियां रुक गईं और कोई अन्य काम उपलब्ध नहीं था। लेकिन यह काम अचानक उपलब्ध हो गया क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने उनसे संपर्क किया जो पहले से ही घर-घर कचरा संग्रहण का काम कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भले ही सब कुछ बंद था, लेकिन कचरा संग्रहण जारी था - "सब कुछ बंद था तब, पर कचरा उठाने का काम चल रहा था, वो कभी बंद नहीं होगा"।

वेतन और सामाजिक सुरक्षा

चूँकि कर्मचारी नगरपालिका कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र अनुबंध कर्मचारी हैं, इसलिए जब वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभों की बात आती है तो उन्हें विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिकों को जोड़े में काम पर रखा जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से पति और पत्नी शामिल होते हैं। जोड़े में काम करने वालों में से, लगभग 90 प्रतिशत लगभग 12,000 से 20,000 रुपये की

चार्ट 6 - अनुबंध पर रखे गए जोड़ों के मासिक वेतन का प्रतिनिधित्व करता है

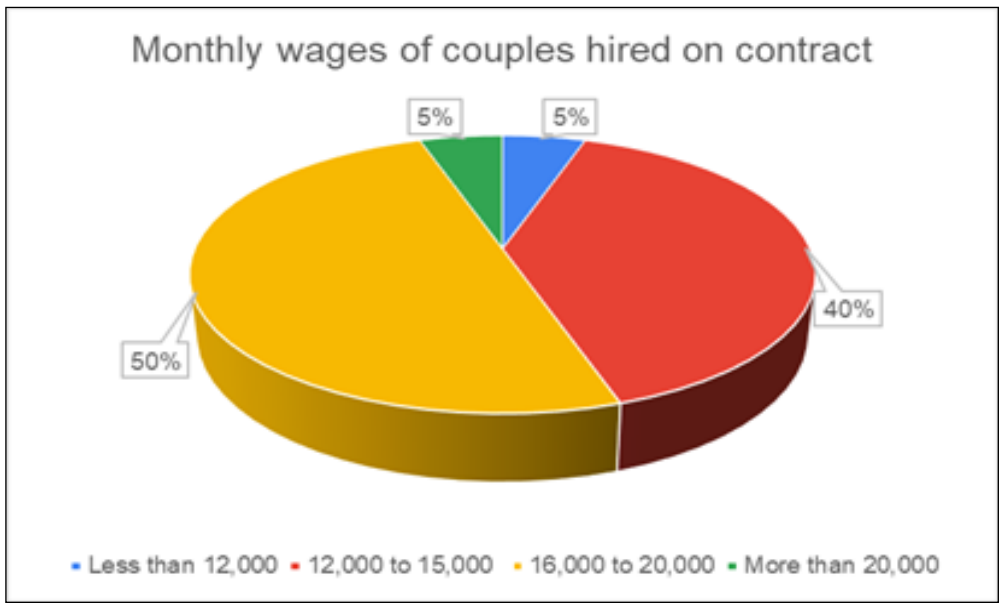

मासिक मजदूरी कमा रहे थे। कुछ मामलों में सीमा एकत्र किए गए कचरे के वजन पर निर्भर थी। यह प्रति व्यक्ति लगभग 6,000 से 10,000 रुपये या 30 दिनों के काम के लिए प्रति दिन 200 से 333 रुपये बैठता है, जो न्यूनतम वेतन से कम है।

गांधीनगर बस्ती के श्रमिकों ने संकेत दिया कि उन्हें प्रत्येक माह की 15वीं या 16वीं तारीख को वेतन मिलता है। जबकि अहमदाबाद में बस्ती के

श्रमिकों ने साझा किया कि जो कर्मचारी ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हैं उन्हें हर दो महीने में वेतन मिलता है और जिगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलता है। इस बस्ती के श्रमिकों ने संकेत दिया कि जहां उनमें से कुछ को एक निश्चित मुआवजा मिलता है, वहीं कुछ को एकत्र किए गए कचरे के वजन के आधार पर राशि मिलती है। यह कोई निश्चित राशि नहीं है और इसमें हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये के बीच उतार-चढ़ाव हो सकता है। अगर वजन ज्यादा है तो उन्हें ज्यादा वजन मिलता है। एक कर्मचारी ने साझा किया कि कई बार कुछ लोग समान घंटे काम करने के बावजूद एक महीने में केवल 5,000 से 7,000 रुपये ही कमाते हैं।

कम मासिक वेतन को पूरा करने के लिए, वे एकत्र किए गए कचरे को छांटने और थोक विक्रेताओं को स्क्रैप बेचने का अतिरिक्त काम भी करते हैं ताकि लगभग 150 से 400 रुपये की दैनिक आय प्राप्त हो सके, जिसे भंगार के रूप में जाना जाता है। यह अतिरिक्त आय उन्हें अपने दैनिक जीवन-यापन के खर्चों को बनाए रखने में मदद करती है। कुछ श्रमिकों ने संकेत दिया कि जब उन्हें उनके बैंक खातों में वेतन प्राप्त होता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा राशि निकाल ली जाती है और नकद श्रमिक परिवारों को सौंप दिया जाता है। कर्मियों का एटीएम कार्ड व पासबुक सुपरवाइजर के पास रहता है। इससे ऐसी स्थिति बनती है जिसमें पर्यवेक्षक भविष्य निधि के नाम पर कुछ राशि काट सकता है और शेष नकदी श्रमिकों को सौंप

सकता है। छप्पन प्रतिशत श्रमिकों ने संकेत दिया कि उन्हें सीधे नकद में पैसा मिल रहा है, जबकि 41 प्रतिशत ने बताया कि यह पहले उनके खातों में जमा किया जा रहा था और बाद में उन्हें नकद में दिया जा रहा था।

ऐसी ही स्थितियाँ सूरत की बस्तियों में पाई गईं। एक बस्ती में मजदूरों के पासबुक और एटीएम कार्ड रोक लिए गए हैं - "बस आधार और पैन कार्ड दिया है हमें, बाकी सुपरवाइजर ने रख लिया है"। पूरे सूरत में, यह पाया गया कि इस बस्ती में श्रमिकों को सबसे कम भुगतान किया जा रहा था; कूड़ा उठाने वाले को 5,500 रुपये और ड्राइवर को 7,000 रुपये। साथ ही, पिछले छह महीने का वेतन लंबित था और श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया था। "कचरा बेचके खर्चा निकालते हैं" - श्रमिकों ने कहा कि वे कबाड़ बेचकर अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में सक्षम थे। गौरतलब है कि सूरत में श्रमिकों के लिए स्क्रैप को ट्रांसफर स्टेशनों पर ही बेचना अनिवार्य है। मजदूरों ने बताया कि अगर कोई बाहर कबाड़ बेचते दिख जाता है तो उसे तुरंत काम से हटा दिया जाता है. पूर्व में ओम स्वच्छता कॉर्पोरेशन के साथ काम करने वाले एक पर्यवेक्षक ने दावा किया कि कंपनी प्रति वाहन 22,500 रुपये का भुगतान करती है, यानी तीन श्रमिकों (एक ड्राइवर, दो सहायक) के लिए। लेकिन चूंकि दस्तावेज़ रोके गए हैं, इसलिए पर्यवेक्षक उन्हें नकद में केवल 18,500 रुपये का भुगतान करते हैं।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ कर्मियों को बताया गया कि भविष्य निधि उनके नाम पर जमा की जा रही है, इसलिए उन्हें दी जाने वाली नकदी से हर महीने 1,000 से 2,000 रुपये की कटौती की जा रही है. हालाँकि, श्रमिकों ने बताया कि ठेकेदारों या पर्यवेक्षकों ने उन्हें कोई खाता संख्या प्रदान नहीं की थी जिसके माध्यम से वे पुष्टि कर सकें कि भविष्य निधि में कटौती की जा रही है या नहीं और उनके खाते में कितनी शेष राशि जमा हुई है।

चार्ट 7 - श्रमिकों को भुगतान के तरीके का प्रतिनिधित्व करना

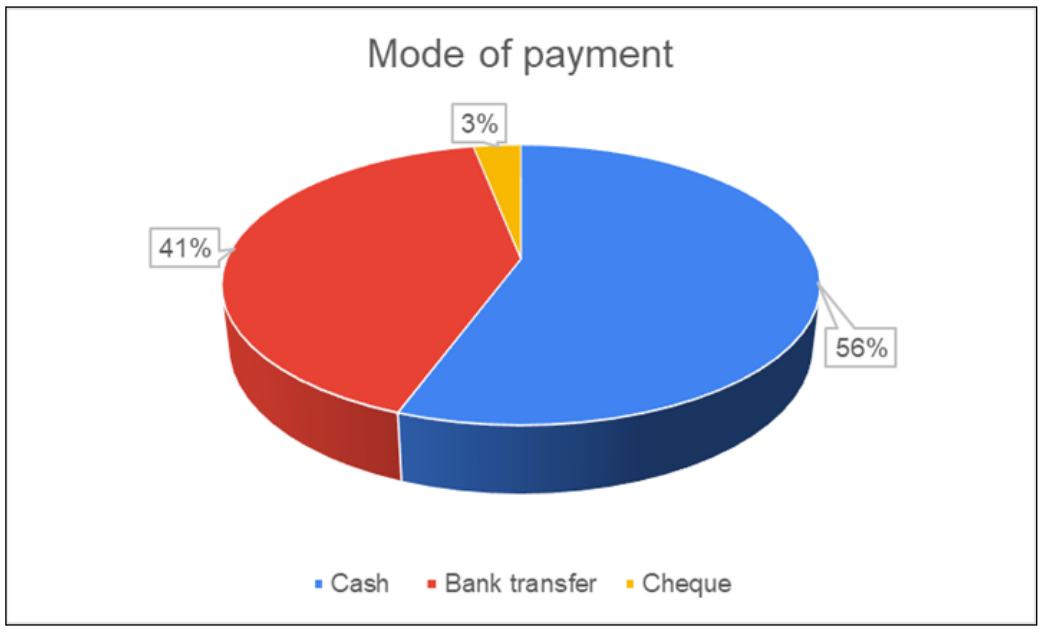

लगभग 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। जबकि 30 प्रतिशत ने संकेत दिया कि उन्हें भविष्य निधि कटौती के बारे में बताया गया था, हालांकि, उन्हें राशि के बारे में पता नहीं था और न ही उन्हें इसके लिए कोई खाता संख्या या विवरण प्रदान किया गया था। नमूना आबादी में से लगभग 12 प्रतिशत ने साझा किया कि उन्हें बताया गया था कि उनके नाम पर 500 से 2,000 रुपये तक की भविष्य निधि जमा की जा रही है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि मजदूरी उनके परिवार के लिए पर्याप्त है, झाबुआ, मध्य प्रदेश के श्रमिकों में से एक ने कहा कि यह उनके लिए दिन में एक बार के भोजन का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त है जो वे पकाते हैं। त्योहारों के दौरान वापस जाने पर वे घर पर भी कुछ पैसे दे सकते हैं। अहमदाबाद बस्ती के श्रमिकों ने बताया कि उन्हें किसी तरह इस राशि से शहर में गुजारा करना है और उन्हें नहीं लगता कि यह उनके श्रम के मूल्य के लिए पर्याप्त है। झाबुआ, एमपी की एक महिला ने कहा कि इस काम के महत्व और श्रम को देखते हुए, उन्हें हर महीने कम से कम 50,000 रुपये मिलने चाहिए। उन्होंने साझा किया कि जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं और अपर्याप्त वेतन के कारण, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता है - "दिन में रोटी भी नहीं खाते हैं। सिर्फ पेट भरने के लिए पानी पीते रहते हैं"। गांधीनगर बस्ती के श्रमिकों ने दोहराया कि उन्हें दिन में एक समय के भोजन पर जीवित रहना पड़ता है।

अहमदाबाद बस्ती के श्रमिकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यदि वाहन का टायर पंक्चर हो जाता है या क्लच प्लेट खराब हो जाती है, तो उसे ठीक करने का खर्च भी श्रमिकों द्वारा वहन किया जाता है। कंपनी या ठेकेदार उसका भुगतान नहीं करता है और सिर्फ डीजल का पैसा देता है। कर्मियों ने बताया कि उन्हें संदेह है कि इसके लिए

चार्ट 8 - उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रतिनिधित्व करना

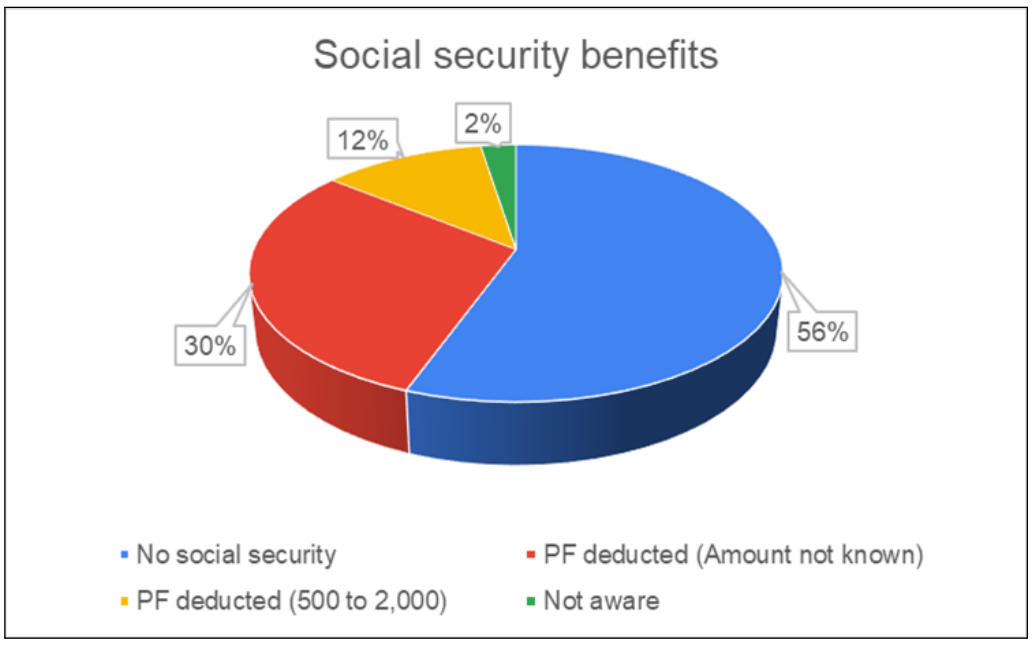

राशि सरकार से आती है, लेकिन उन तक नहीं पहुंचती। इसके अलावा, यदि वे किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो दोष पूरी तरह से कर्मचारी पर होगा। कचरा संग्रहण वाहन आने की घोषणा करने के लिए उपकरण खरीदने का खर्च - जिसमें माइक्रोफोन, टेप और सीटी शामिल है, भी श्रमिकों द्वारा वहन किया जाता है। कंपनी ने सिर्फ गाड़ी उपलब्ध करायी है.

श्रमिकों ने आगे कहा कि अगर उन्हें सीधे सरकार द्वारा नियोजित किया जाता, तो कम से कम उन्हें नौकरी की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, बीमा और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते। एक कर्मचारी ने कहा कि एक निजी अनुबंध में, उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकारी नौकरी में सुरक्षित रोजगार होता है और यह निश्चित होता है कि भविष्य में कर्मचारी को कुछ भी हो जाए तो उनके परिवार और बच्चों के पास रहने के लिए कुछ न कुछ होगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

काम करने की स्थितियाँ और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

अहमदाबाद की एक बस्ती में रहने वाले मध्य प्रदेश के झाबुआ के श्रमिकों ने बताया कि उनमें से कुछ काम के लिए सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, जबकि कुछ सुबह 5-6 बजे के आसपास जाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस क्षेत्र को कवर करना है। अक्सर, ड्यूटी लगभग 12 घंटे तक बढ़ जाती है। वे दिन के दौरान आराम नहीं करना पसंद करते हैं क्योंकि लगातार काम करने से वे समय पर बस्ती वापस आ सकेंगे। नमूनाकृत जनसंख्या के बीच, कार्य-दिवस की औसत लंबाई लगभग 11 घंटे बताई गई, लगभग 85 प्रतिशत ने संकेत दिया कि उनका कार्य-दिवस आठ घंटे से अधिक है। श्रमिकों ने बताया कि उन्हें सप्ताह के दौरान कोई छुट्टी नहीं मिलती है और यदि वे त्योहारों के दौरान घर वापस जाने के लिए छुट्टी लेते हैं, तो उन्हें उस समय का वेतन नहीं मिलता है और उनकी अनुपस्थिति में काम जारी

चार्ट 9 - एक दिन के दौरान काम के घंटों को दर्शाता है

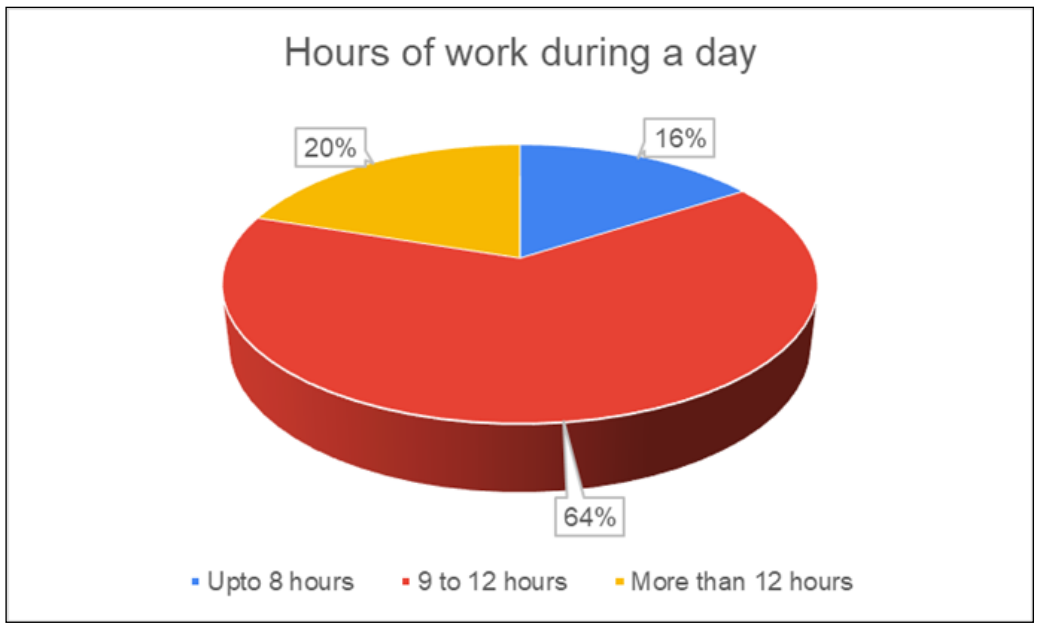

रखने के लिए उन्हें एक प्रतिस्थापन रखना पड़ता है।

सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश श्रमिकों ने संकेत दिया कि वे दस्ताने, मास्क या जूते जैसे किसी भी सुरक्षात्मक गियर के बिना काम कर रहे थे। नमूना आबादी में से, लगभग 65 प्रतिशत ने संकेत दिया कि उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किया गया था, जबकि शेष 35 प्रतिशत ने संकेत दिया कि उन्हें वर्दी, दस्ताने, जूते, मास्क और साबुन जैसे उपकरण प्राप्त हुए थे। गांधीनगर और अहमदाबाद की बस्तियों में महिलाओं ने बताया कि कभी-कभी उनके हाथों में सीरिंज, सुई और कांच चुभ जाते हैं। उनका मानना था कि लोगों को यह समझ नहीं है कि इन चीजों का निपटान कैसे किया जाए। इस कचरे का अधिकांश हिस्सा सीधे तौर पर महिलाओं द्वारा संभाला जाता है, जिससे वे असुरक्षित स्थिति में आ जाती हैं। कचरे को छांटने के लिए उन्हें अपने साथ एक छड़ी रखनी पड़ती है ताकि जितना संभव हो कचरे को सीधे छूने से बचा जा सके, हालांकि, यह अपरिहार्य हो जाता है। कुछ महिलाओं ने बताया कि कई बार लोग चार से पांच दिनों तक कूड़ा जमा करने के बाद उसे फेंक देते हैं, जिससे बदबू बढ़ जाती है, जिससे उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इसके अलावा, श्रमिकों को जो दस्ताने उपलब्ध कराए गए थे वे कपड़े के बने थे और घटिया गुणवत्ता और खराब फिटिंग के थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, हालांकि, यह बोझिल था क्योंकि गीले कचरे से दस्ताने खराब हो जाते थे और उन्हें पहनकर काम करना मुश्किल हो जाता था। इस कारण से, कचरा संग्रहण और पृथक्करण के दौरान कोई भी दस्ताने नहीं पहनता है। उन्हें लगा कि रबर के दस्ताने बेहतर होते। श्रमिकों को मास्क भी दिए गए थे, हालांकि मौसम की स्थिति को देखते हुए मास्क पहनना जारी रखना असुविधाजनक था। एक कार्यकर्ता ने बताया कि उन्हें केवल एक मास्क दिया गया था, जो डिस्पोजेबल था और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक कार्यकर्ता ने

चार्ट 10 - उत्तरदाताओं को सुरक्षा प्रावधानों का प्रतिनिधित्व

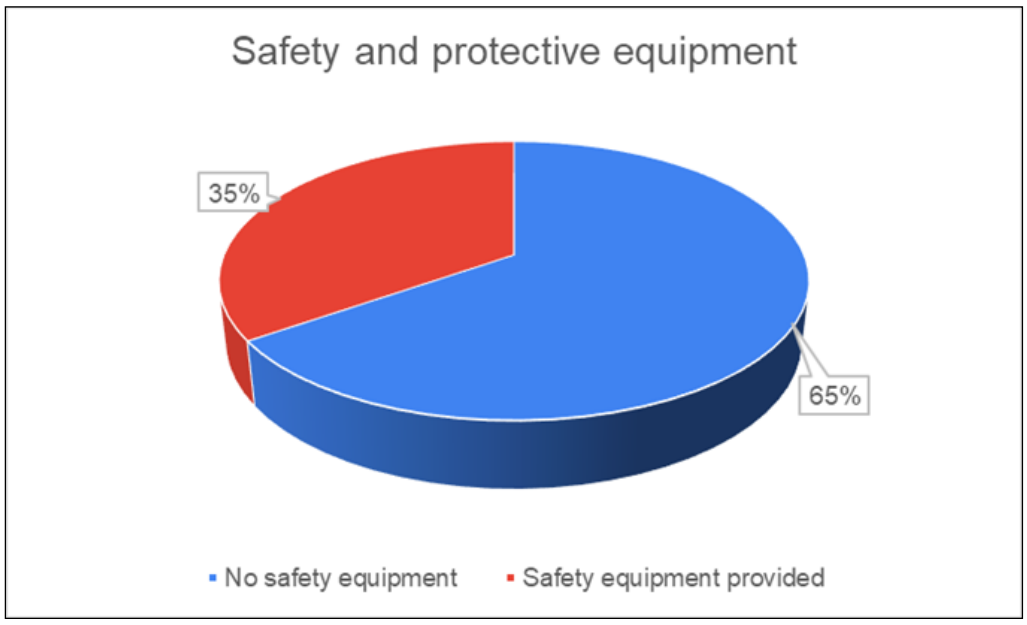

कहा, "दिया था सुरक्षा के लिए, फिर फोटो खींच के चले गए"। अहमदाबाद बस्ती के श्रमिकों ने यह भी बताया कि शुरुआत में उन्हें दस्ताने और मास्क समेत कुछ सुरक्षा उपकरण मिले थे, लेकिन उनका उपयोग करना संभव नहीं था और शुरुआती उपयोग के कारण वे बर्बाद हो गए, जिसके बाद कंपनी ने उनकी भरपाई नहीं की। इसके अलावा, कंपनी ने उन्हें एक वर्दी प्रदान की, जिसके लिए उन्होंने श्रमिकों से शुल्क मांगा। सर्वेक्षण में शामिल 196 श्रमिकों में से लगभग 98 प्रतिशत ने साझा किया कि उन्हें इस काम के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं मिला और उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सभी कौशल खुद ही सीखने पड़े।

श्रमिकों ने संकेत दिया कि काम के कारण वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनका चिकित्सा खर्च बढ़ जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अक्षमता और देखभाल की खराब गुणवत्ता के कारण, उन्हें निजी अस्पताल में जाना पड़ता है जिससे उनका जेब खर्च बढ़ जाता है। महिला श्रमिकों में से एक ने बताया कि वह तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण अस्पताल गई थी और उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी कीमत 600 रुपये थी। इस काम के साथ बीमार पड़ने से बचना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे लगातार कचरे के संपर्क में आती हैं। तेज़ बुखार, पेट में संक्रमण, त्वचा संबंधी समस्याएँ और साँस लेने में समस्याएँ आम बीमारियाँ हैं जिनसे वे पीड़ित हैं। इसके अलावा, उनकी रहने की स्थिति भी उन्हें असुरक्षित स्थिति में डाल देती है। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनके स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करना उनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं है। कम वेतन और समय की कमी को देखते हुए, उन्हें दिन में केवल एक बार ही उचित भोजन मिलता है, जिससे उन्हें पोषण और कैलोरी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद नहीं मिलती है। उन्हें कोई स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिला और उन्हें अपनी स्वास्थ्य देखभाल लागत की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ी। मजदूरों ने बताया कि पिछले वर्ष उनकी बस्ती में केवल एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जहां लगभग 250 परिवारों को इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आया था। कार्यकर्ताओं ने साझा किया कि इन मुद्दों का प्रभाव समय के साथ दिखाई दे सकता है, तुरंत नहीं। "बीमार तो होना ही है। अभी पता नहीं चलेगा।"।

महिला कचरा संग्रहकर्ताओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियाँ

घर-घर कचरा संग्रहण कार्य में लगी महिला श्रमिकों को घरेलू काम और कचरे के संग्रहण और छंटाई के दोहरे बोझ का अनुभव होता है, जबकि उनके पति वाहन चलाते हैं। इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के बावजूद, महिलाओं को अदृश्य बना दिया जाता है क्योंकि उप-ठेकेदार पति और पत्नी के जोड़े को काम पर रखते हैं और सभी सौदे पति के नाम पर होते हैं और महिलाओं को सीधे मजदूरी नहीं मिलती है। यह काम को समझने में लैंगिक पूर्वाग्रह को भी दर्शाता है जिसमें भारी वाहन चलाने के काम को "कुशल" के रूप में देखा जाता है और कचरे को इकट्ठा करने और छांटने के काम को "अकुशल" श्रम के रूप में माना जाता है।

अक्सर, श्रमिकों के साथ उनके चार साल से कम उम्र के बच्चे भी होते हैं क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। बड़े

बच्चे शिक्षा के लिए स्रोत स्थान पर ही रहते हैं। गंतव्य पर बच्चे, आंगनवाड़ी या स्कूलों की कमी को देखते हुए, वाहन में माता-पिता के साथ जाते हैं। हालाँकि महिलाओं ने कहा कि इस काम के लिए बच्चों को वाहन में ले जाना निर्माण स्थलों पर ले जाने की तुलना में आसान है, फिर भी जहरीले कचरे के नजदीक होने के कारण बीमारियाँ होने का डर बना रहता है। हालाँकि, उन्हें बस्ती में नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि खुले में अकेले छोड़ने पर कुत्ते उन्हें काट सकते हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा कार्यकर्ताओं को यह भी कहा गया था कि वे बच्चों को अपने साथ वाहन में न ले जाएं, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि कोई आंगनवाड़ी या स्कूली शिक्षा सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। अहमदाबाद में बस्ती के श्रमिकों ने साझा किया कि यदि उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जाती है और बच्चों की सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने वाला कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता है, तो वे अपने बच्चों को वहीं छोड़ना पसंद करेंगे। सर्वेक्षण में शामिल 196 श्रमिकों में से केवल दो ने किसी भी प्रकार का मातृत्व लाभ प्राप्त होने का संकेत दिया।

कूड़ा-कचरा छांटकर कबाड़ इकट्ठा करने का काम महिलाएं करती हैं जबकि पुरुष वाहन चलाता है। यह काम इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे उन्हें भंगार

बेचकर रोजाना की कमाई हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान, अक्सर महिलाओं को कचरे में कांच, ब्लेड, या सीरिंज और सुइयों की उपस्थिति के कारण अपने हाथों को चोट लग जाती है। यहां तक कि बचे हुए खाने का निपटारा भी महिलाएं अपने हाथों से करती हैं और कई बार कूड़ा चार से पांच दिन पुराना होता है, जिससे दुर्गंध असहनीय हो जाती है। यह पूछे जाने पर कि अगर दिन में कचरा इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते समय उन्हें शौचालय का उपयोग करना पड़ता है तो वे क्या करती हैं, अहमदाबाद बस्ती की महिला श्रमिकों ने बताया कि रास्ते में उन्हें शौचालय तक पहुंच नहीं मिलती है क्योंकि वहां शायद ही कोई चालू सार्वजनिक शौचालय है। कुछ सोसाइटियों को छोड़कर, जो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शौचालय उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें सोसायटी में शौचालयों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। परिणामस्वरूप, अधिकांश मामलों में उन्हें खुले में शौच करना पड़ता है।

महिला श्रमिकों से बातचीत के दौरान बस्तियों की महिलाओं ने बताया कि उन्हें हर दिन सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। सुबह में, सामान्य नल से पानी भरने के बाद, वे परिवार के लिए चाय बनाते हैं और सुबह 6 बजे के आसपास काम पर निकल जाते हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि चूंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है, इसलिए वे सुबह चाय भी नहीं बना पाती हैं और उन्हें बाहर की दुकानों से चाय पीनी पड़ती है और कुछ खाना पड़ता है। प्रत्येक वैन औसतन लगभग पाँच सोसायटियों को कवर करती है। कुछ के पास कवर करने के लिए अधिक सोसाइटी हो सकती है और इसमें अधिक समय लगता है। पुरुष वाहन चलाते हैं और महिलाएं उतरती हैं और प्रत्येक घर से एकत्र किए गए कचरे से वाहन भरती हैं। जब कूड़ा एक जगह एकत्र नहीं होता है, तो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक घर तक चलने की प्रक्रिया उनके लिए थका देने वाली हो जाती है। शॉपिंग मॉल और बड़ी हाउसिंग सोसायटियों में कचरा बाहर बड़े कूड़ेदान में रखा जाता है। इन सोसायटियों द्वारा नियुक्त हाउसकीपिंग स्टाफ प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करता है और उसे सामान्य कूड़ेदान में जमा करता है। हालाँकि, अन्य इलाकों में, प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करना पड़ता है। कचरा एकत्र करने के बाद, महिलाएं कचरे को वाहन में ही अलग कर देती हैं, कभी-कभी वाहन चलते समय भी।

महिला श्रमिकों में से एक ने बताया कि कुछ घर रेत और अन्य भारी सामग्रियों को भी कचरे के रूप में फेंक देते हैं, जिन्हें उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है। यह शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। एक और चुनौती सैनिटरी नैपकिन और डायपर जैसे स्वच्छता उत्पादों को चुनना है - जो रक्त, मूत्र और मल से दूषित होते हैं, जिनका अक्सर ठीक से निपटान नहीं किया जाता है। श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए वाहनों में सैनिटरी

कचरे के लिए पीछे एक बाल्टी लटकाई जाती है। हालाँकि, श्रमिकों के अनुसार, जब वाहन चल रहा था तो यह गिर गया। इसलिए, सैनिटरी कचरा भी अन्य कचरे की तरह ही उसी डिब्बे में जाता है।

काम से घर पहुंचने के बाद, महिलाएं खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना और कपड़े और बर्तन धोना जैसे अन्य कार्य करती हैं। वे रात को करीब 11 बजे सो जाते हैं. "हमें आराम से बैठने का कोई समय नहीं मिलता। आदत पढ़ गई है तो करते रहते हैं" । औसतन, जो महिलाएं नमूना आबादी का हिस्सा थीं, उन्होंने घरेलू काम पर दो से तीन घंटे खर्च करने का संकेत दिया।

श्रमिकों को उत्पीड़न और कलंक का सामना करना पड़ा

शुद्धता और प्रदूषण की धारणा पर कायम जाति के प्रस्थापनाओं ने कचरा बीनने वालों के काम को कलंकित कर दिया है, जो आम तौर पर दलित या आदिवासी होते हैं। इस प्रकार, काम से जुड़े कलंक के साथ-साथ उन्हें जाति-आधारित भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है (कोर्नबर्ग, 2019; रंगनाथन, 2022; श्रीनाथ, 2019, जैसा कि विटमर, 2021 में उद्धृत किया गया है)। अनौपचारिक रोजगार में महिलाएँ: वैश्वीकरण और आयोजन (डब्ल्यूआईईजीओ) द्वारा कचरा श्रमिकों पर किए गए

एक अध्ययन में बताया गया है कि 47 प्रतिशत कचरा श्रमिकों ने काम पर उत्पीड़न को उनके काम में बाधा डालने वाले सबसे अधिक प्रभावित मुद्दों में से एक के रूप में दर्शाया है (चड्ढा, 2020)।

श्रमिकों के साथ चर्चा से ठेकेदारों, पर्यवेक्षकों या निगम अधिकारियों के बजाय उन घरों के निवासियों के साथ भेदभाव के अधिक उदाहरण सामने आए जहां से उन्होंने कचरा एकत्र किया था। हैरिस-व्हाइट (2015) कचरा प्रबंधन श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में लिखते हैं कि ये उनके काम की वास्तविकताओं के परिणामस्वरूप होता है, न कि उनकी जाति आधारित पहचान के कारण। यह बात घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में दिखाई देती है जो इस अध्ययन का हिस्सा हैं। एसटी समुदाय ऐतिहासिक रूप से कचरा प्रबंधन कार्य में शामिल नहीं हैं। शहरी निवासियों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वह उनके काम की प्रकृति का एक उत्पाद प्रतीत होता है जो उन्हें निम्न स्थिति में धकेल देता है। न केवल कार्यस्थल पर, श्रमिकों ने अपने मूल गांवों में भी अपने समुदायों के बीच इस भेदभाव का अनुभव करने के बारे में बात की। उनके गांवों में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं, वे इस काम को अपनाने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। जबकि उनकी समूह-आधारित पहचान के कारण सामना की जाने वाली भौतिक और सामाजिक स्थितियाँ उन्हें कचरे के काम की ओर ले जा रही हैं, दिन-प्रतिदिन के आधार पर उनके द्वारा अनुभव किया जाने वाला व्यक्तिगत भेदभाव काम की स्थितियों के कारण बढ़ गया है, न कि केवल उनकी आदिवासी पहचान के कारण.

इससे जुड़े कलंक के बावजूद, इस काम में आने के कारणों के बारे में बात करने पर, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की महिला श्रमिकों ने बताया कि घर-घर कचरा संग्रहण की तुलना में निर्माण कार्य अधिक श्रमसाध्य और जोखिम भरा था। इसके अलावा, स्क्रैप बेचकर वे जो दैनिक आय अर्जित कर सकते हैं, उससे प्राप्त मासिक वेतन को बचाया जा सकता है, जो निर्माण क्षेत्र में दैनिक मजदूरी के काम में संभव नहीं है। महिलाओं ने आगे बताया कि अपने बच्चों को कचरा संग्रहण कार्य के लिए वाहन में ले जाने की तुलना में नाकों और निर्माण स्थल पर ले जाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। उन्होंने पाया कि यह काम निर्माण कार्य की तुलना में भौतिक रूप से अधिक व्यवहार्य है

जिसमें भारी सामग्री लोड करना और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करना शामिल है। अहमदाबाद में बस्ती के श्रमिकों ने यह भी साझा किया कि नियोक्ता हिंसा के मामले में, उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी के पर्यवेक्षकों के साथ उनकी दैनिक बातचीत की तुलना में निर्माण स्थल पर अधिक मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। हालाँकि, श्रमिकों ने कहा कि इसके बावजूद लोगों के रवैये के कारण यह काम "गंदा" है और इसमें कई चुनौतियाँ हैं। अहमदाबाद में बस्ती की महिला श्रमिकों ने यह भी साझा किया कि वे काम को "गंदा" नहीं मानती हैं, लेकिन यह काम के बारे में लोगों की धारणा है जिसके कारण काम को आगे बढ़ाने में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से वेतन भी अपर्याप्त है और कबाड़ बेचकर ही गुजारा होता है।

मजदूरों ने ऐसे उदाहरण भी साझा किए जिनमें लोग कचरा इकट्ठा करने के बाद गेट बंद करना भूल जाने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे और उन पर चिल्लाते थे। कुछ लोगों ने कभी-कभी घर में रहने वाले लोगों के नशे में होने पर थप्पड़ मारने जैसे शारीरिक शोषण की बात भी कही। काम जारी रखने और अपनी नौकरी न खोने के लिए, श्रमिकों को विनम्र रहना होगा और प्रतिशोध नहीं लेना होगा। यदि वे थोड़ा सा भी प्रतिकार करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि उन्हें काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए और काम करना जारी रखना

चाहिए। यदि उनके काम के दौरान किसी विवाद में पड़ जाते हैं तो अनुबंध करने वाली इकाई में से कोई भी उनका समर्थन नहीं करेगा, इसलिए वे आम तौर पर सहन करते हैं। यदि वे प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के बजाय एक सामान्य स्थान पर कचरा एकत्र करने का अनुरोध करते हैं, तो पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं और उन्हें यह काम करने के लिए कहते हैं क्योंकि वे इसके लिए पैसे ले रहे हैं और समाज के निवासी इस काम के लिए कर का भुगतान करते हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा, "वैसे तो हम भी जंगल के रहने वाले हैं, हम किसी से नहीं डरते, पर अब क्या करें मजबूरी है। कोई छोटा बच्चा भी डराएगा तो डरना पढ़ता है" . श्रमिकों में से एक ने कहा कि अंततः वे बाहरी हैं क्योंकि वे काम के लिए दूसरे राज्य से आए हैं, और उनके काम के दर्जे के कारण उन्हें शहर में कभी भी अपनेपन की भावना नहीं होगी।

रहने की स्थिति

अनुसंधान दल ने कचरा प्रबंधन कर्मियों की जिन बस्तियों का दौरा किया, वे अवैध बस्तियां थीं जो घर

-घर कचरा संग्रहण में तैनात वाहनों की पार्किंग के लिए ठेकेदार को प्रदान किए गए क्षेत्रों में स्थित थीं। इस बस्ती में बांस और तिरपाल शीट से बनी झोपड़ियाँ या कच्चे घर शामिल हैं। श्रमिकों ने बताया कि बारिश के दौरान घर के अंदर पानी घुस जाता है और बस्ती में पानी जमा होने से दैनिक कार्य करना भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गांधीनगर की एक बस्ती में, पास के बिजली संयंत्र से निकलने वाला धुआं एक शाश्वत वास्तविकता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आंखों और त्वचा में खुजली भी होती है। तीनों शहरों में सर्वेक्षण में शामिल 94 प्रतिशत श्रमिकों ने कच्चे घरों में रहने का संकेत दिया।

बस्ती में अपने आवास के लिए, गांधीनगर बस्ती के श्रमिकों ने साझा किया कि ठेकेदार ने उन्हें अपनी झोपड़ियाँ स्थापित करने के लिए जमीन प्रदान की थी, और उन्हें किराया, पानी या बिजली के लिए कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, अहमदाबाद बस्ती के कुछ श्रमिकों ने 500 रुपये प्रति माह के किराए पर एक बस्ती में अर्ध-पक्के कमरे ले लिए हैं। अध्ययन के हिस्से के रूप में सर्वेक्षण किए गए अधिकांश बस्तियों में सुरक्षित शौचालय नहीं थे और निवासियों को खुले में शौच का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा था। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 91 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्हें बस्ती में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, अहमदाबाद और गांधीनगर में अनुसंधान दल द्वारा दौरा की गई चार अवैध बस्तियों में से तीन में बिजली की पहुंच नहीं है। कुछ निवासी बुनियादी जरूरतों के लिए बैटरियां खरीदते हैं। चूल्हे की रोशनी में खाना बनता है। इन बस्तियों में श्रमिकों

चार्ट 11 - उत्तरदाताओं की आवास स्थिति का प्रतिनिधित्व

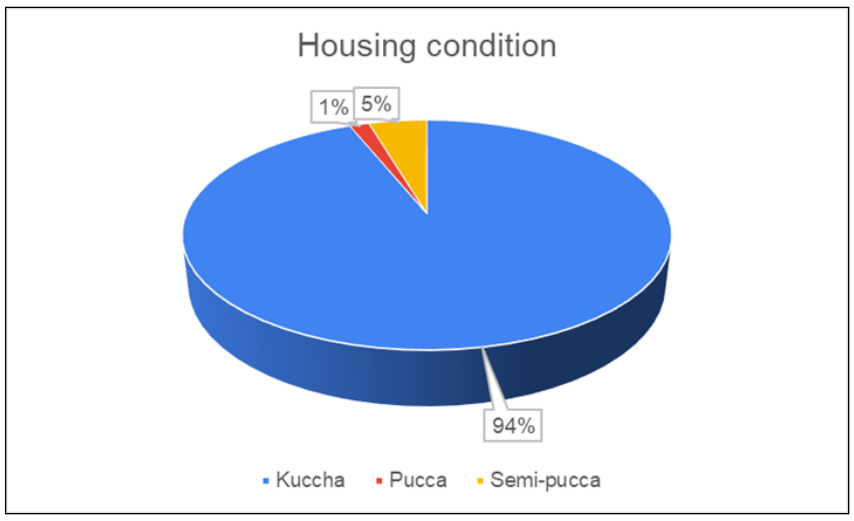

चार्ट 12 - श्रमिक परिवारों द्वारा भुगतान किए गए मासिक किराए का प्रतिनिधित्व

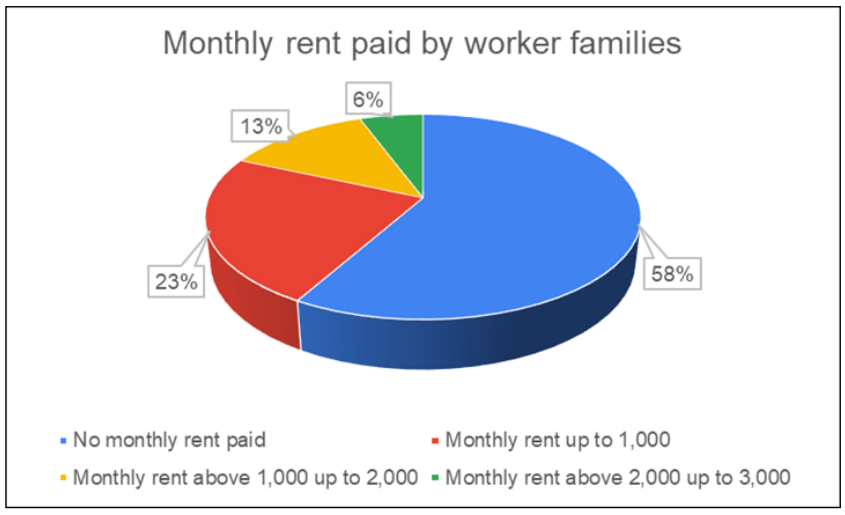

को नियमित जल आपूर्ति नहीं है और वे पानी के टैंकरों और निजी नलों जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हैं। सुबह पानी इकट्ठा करने और जमा करने का बोझ घर की महिलाओं पर आ गया। उन्होंने उल्लेख किया कि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना जीवन स्थितियों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है जिसका वे सामना कर रहे हैं। कभी-कभी जब उनकी नियमित आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, तो उन्हें पानी की तलाश में किसी अन्य क्षेत्र में जाना पड़ता है।

अहमदाबाद बस्ती के श्रमिकों ने बताया कि चूंकि उन्हें खुले में सोना पड़ता है, इसलिए उन्हें मच्छर काट लेते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य नियमित रूप से खराब हो जाता है। निगम से किसी ने भी घूमन के लिए या श्रमिकों की रहने की स्थिति की जांच करने के लिए बस्तियों का दौरा नहीं किया है। शोध के दौरान, अहमदाबाद की एक बस्ती को बेदखल करने की धमकी मिली, हालाँकि, इस रिपोर्ट को तैयार करने के

चार्ट 13 - शौचालय उपलब्धि

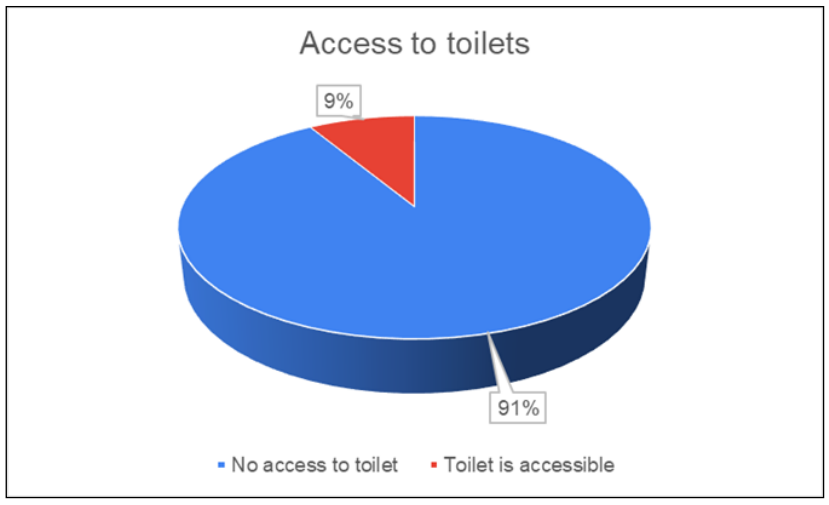

समय तक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

असंगठित कर्मी

SEWA के एक अध्ययन के अनुसार, अहमदाबाद में लगभग 50,000 अनौपचारिक कचरा श्रमिक हैं, जिनमें से इसने लगभग 30,000-40,000 को संगठित किया है। अहमदाबाद में कचरा बीनने वाली 25,000 से अधिक महिलाएँ SEWA (ओट्स एट अल., 2018) से जुड़ी हैं। हालाँकि, घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले श्रमिकों की यूनियनों, सामूहिकों या सहकारी समितियों की कमी है। वास्तव में, पूरे कचरा प्रबंधन क्षेत्र के भीतर, किसी भी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने ट्रेड यूनियन का गठन नहीं किया है (ईश्वरन और हमीदा, 2013)। सर्वेक्षण में शामिल 196 श्रमिक परिवारों में से केवल पांच ने किसी भी प्रकार के संगठन या संघ का हिस्सा होने का संकेत दिया। यूनियनीकरण की कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रमिकों को लगता है कि इससे उन्हें अपने मुद्दों और मांगों को सामने रखने में मदद मिलेगी। श्रमिकों ने साझा किया कि उनके लिए अपने अधिकारों की मांग के लिए किसी आंदोलन में शामिल होना तभी संभव होगा जब अधिकांश श्रमिक इसका हिस्सा होंगे। अन्यथा, उनकी पहचान कर ली जाएगी, उन्हें अलग कर दिया जाएगा और वे अपनी आय का स्रोत खो देंगे और उन्हें अपने गांव वापस जाना होगा। यह जानने के बावजूद, श्रमिक अपनी सामूहिक शक्ति और शहर और उसके नागरिकों के लिए अपने काम के मूल्य से अवगत थे।

अध्याय 6

समापन टिप्पणी और आगे का रास्ता

घरों और प्रतिष्ठानों से उत्पन्न कचरे से पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को एकत्र करने, छांटने और पुनर्प्राप्त करने के कार्य के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में कचरा प्रबंधन कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। हालाँकि, अध्ययन इस क्षेत्र में श्रमिकों की गंभीर कामकाजी और जीवन स्थितियों पर प्रकाश डालता है। जैसा कि हैरिस-व्हाइट (2015) का तर्क है कि कचरा प्रबंधन कार्य में शामिल श्रमिकों की गरिमा सुनिश्चित करने और उनकी सामाजिक और रोजगार स्थितियों में सुधार करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। इसका कारण कचरा प्रबंधन क्षेत्र में जाति का मजबूत होना है। भारत में कचरा प्रबंधन की नीति बनाने में और राजनीतिक अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में श्रमिकों की आवाज़ को शामिल करना अनिवार्य है। जाति-तटस्थ नौकरियाँ, अपेक्षित तकनीकी उन्नयन, और शिक्षा का अवसर और अन्य कार्य करने के लिए विकल्प या गतिशीलता नीतिगत प्राथमिकताएँ होनी चाहिए।

हालांकि यह सच है कि कचरा प्रबंधन के व्यवसाय में दलितों का वर्चस्व रहा है। अन्य उद्योगों में कम होते अवसरों और अपशिष्ट प्रबंधन के आकर्षक

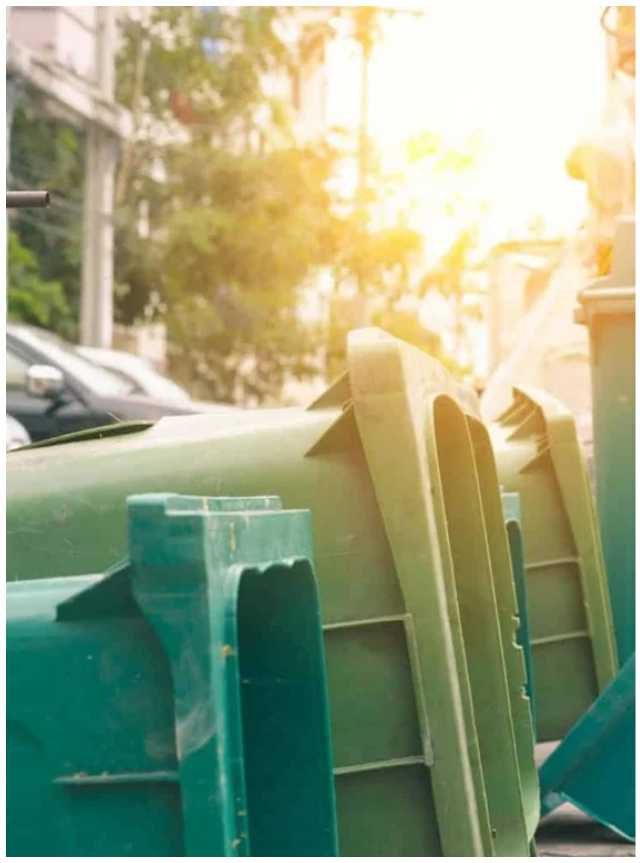

व्यवसाय के कारण अन्य समूहों ने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। यह इस अध्ययन में स्पष्ट हो जाता है जो झाबुआ और दाहोद से गुजरात के शहरों में आदिवासी परिवारों के प्रवास पैटर्न और श्रम के अन्य रूपों से कचरा प्रबंधन कार्य में स्थानांतरित होने के उनके विकल्प पर प्रकाश डालता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि हालांकि गैर-दलितों को सड़क किनारे कचरा बीनने में प्रवेश मिल गया है, फिर भी उन्हें घरेलू सफाईकर्मी या घर-घर कचरा बीनने वाले के रूप में काम करना मुश्किल लगता है। जातिगत नुस्खे और मौजूदा ग्राहक-संरक्षक संबंध ऐसी भूमिकाओं के लिए दलितों के रोजगार को प्राथमिकता देते हैं। अहमदाबाद की रामापीर नो टेकरो बस्ती में, दलितों के पास पीठे हैं, जो कबाड़ बीनने वालों से या सीधे घरेलू घरों से अलग किए गए स्क्रैप सामग्री खरीदने के लिए निर्दिष्ट दुकानें हैं। पिठा अन्य दलित कबाड़ संग्राहकों के सहयोग से चलता है। हालाँकि, पीठावाला के रूप में उनकी स्वीकृति 10-15 वर्षों तक व्यवसाय में रहने के बाद आई (सन्नभदति, 2019)।

यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के भीतर निजीकरण के कारण अनौपचारिक श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसरों का नुकसान व्यावसायिक स्थानों तक उनकी पहुंच पर निर्भर करता है। मित्रा और बागची (2017) ने कोलकाता की एसडब्ल्यूएम प्रणाली पर एक अध्ययन में स्थानों तक पहुंच के सवाल के बारे में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने लाए हैं। घर -घर कचरा संग्रहण को औपचारिक बनाने के प्रयासों ने सड़कों पर कचरा बीनने वालों के पास छांटने और बेचने के लिए उपलब्ध कचरे को भी कम कर दिया है। कचरे के घरेलू संग्रहण की औपचारिकता न केवल पर्यावरणीय चिंताओं से बल्कि लाभ की संभावना से भी उत्पन्न होती है जो कचरे से ऊर्जा निकालने से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा, कचरा प्रबंधन प्रणाली को औपचारिक बनाने का अभियान उन लोगों को अमानवीय बनाता है जिन्हें अकुशल मजदूरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए हमें सचेत रूप से औपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक श्रम शक्ति के स्थायी समावेश से निपटने की आवश्यकता है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां श्रम प्रणालियों के पारंपरिक और

आधुनिक दोनों पहलू समाज में समानांतर रूप से मौजूद हैं।

यदि आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिना श्रम प्रणाली को औपचारिक बनाने के प्रयास किए जाते हैं, तो अधिकारों और अवसरों की आधुनिक प्रणाली, जो कानूनी तंत्रों द्वारा समर्थित और जन्म देती है, अनौपचारिक और औपचारिक श्रम के बीच गहरी फूट पैदा कर सकती है। कचरा प्रबंधन उद्योग में अनौपचारिक श्रम को समझने का एक अन्य पहलू स्व-रोज़गार होने के नाते अपने कार्य इनपुट को नियंत्रित करने के लेंस के माध्यम से होगा (अग्रवाल, 2016)। अनौपचारिक कचरा प्रबंधन उद्योग में वर्षों के अभ्यास से स्थापित परंपराएं हैं जो कचरा खरीदारों और कचरा संग्रहकर्ताओं और विक्रेताओं के बीच विश्वास-आधारित संबंधों पर पनपती हैं। चूंकि वे स्व-रोज़गार व्यक्ति हैं, इसलिए उनका अपने श्रम इनपुट और सौदेबाजी की शक्ति पर नियंत्रण होता है। थाईलैंड पर एक अध्ययन में, अनौपचारिक कचरा संग्रह उद्योग में म्यांमार के प्रवासी श्रमिक अपने मासिक वेतन की प्रतीक्षा किए बिना, स्क्रैप बिक्री के माध्यम से अपनी दैनिक कमाई प्राप्त करते हैं और यह उन्हें पूंजीवादी मानदंडों के प्रति घृणा के अलावा व्यवसाय से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है (कैंपबेल, 2018)। इससे उन्हें वित्तीय बोझ से निपटने में मदद मिलती है, भले ही उनकी कमाई न्यूनतम हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी सामाजिक स्थिति उनके आर्थिक अवसरों में बाधा डालती है या उनके श्रम इनपुट की आवश्यकता को कई गुना बढ़ा देती है।

इस क्षेत्र में कुछ आंदोलन हुए हैं, जिनमें से कुछ से श्रमिकों के लिए सकारात्मक बदलाव आए हैं। 2016 में, कचरा प्रबंधन कर्मचारी स्थायी पदों की मांग को लेकर अहमदाबाद में हड़ताल पर चले गए, जिसमें महिला श्रमिकों की बड़ी भागीदारी थी (सिन्हा, 2016)। 2020 में अहमदाबाद में सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने परिजनों के लिए अनुकंपा नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल भी की गई थी। पुणे की स्व-रोज़गार महिला कचरा प्रबंधन कार्यकर्ता, जिन्होंने खुद को कागद कच पत्र काश्तकारी पंचायत (केकेपीकेपी) में संगठित किया, जो 1993 में कागज, प्लास्टिक और बोतल रिसाइक्लर्स का एक ट्रेड यूनियन था। 2006 में शुरू हुआ SWaCH (ठोस कचरा संग्रह और हैंडलिंग), उनके कार्यकर्ता-स्वामित्व वाली सहकारी संस्था, शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ और समावेशी एसडब्ल्यूएम के लिए एक मॉडल प्रदान

करती है। 2008 में, पुणे नगर निगम द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण के लिए SWaCH को नियुक्त किया गया था। सुधार की गुंजाइश होने के बावजूद, संगठित महिला श्रमिक वेतन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री बेचने से अतिरिक्त आय और एक 'सार्वजनिक सेवक' की पहचान अर्जित करती हैं। श्रमिकों ने शुरू में एक पहचान पत्र की मांग करते हुए और उन्हें कचरा प्रबंधन श्रमिकों के रूप में पंजीकृत करने की मांग करते हुए मार्च में भाग लिया, जिससे बाल श्रम में गिरावट आई। संघ ने गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड, बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई और स्वास्थ्य बीमा की भी मांग की (ब्रूक, 2014; गाडगिल और मेनन जैसा कानेकल, 2019 में उद्धृत किया गया है)। इसके अलावा, बेंगलुरु में एनजीओ हसीरुदाला, जिसे 2013 में स्थापित किया गया था, ने कचरा बीनने वालों के अधिकारों की वकालत करने के प्रयास किए हैं। उनके प्रयासों के कारण, 2019 तक, बेंगलुरु में लगभग 7,500 कचरा बीनने वालों को आधिकारिक पहचान पत्र के साथ नगरपालिका श्रमिकों के रूप में पंजीकृत किया गया था (कानेकल, 2019)।

यह अध्ययन बताता है कि वर्तमान में, अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारियों के पास कोई संघ नहीं है जो उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने में मदद कर सके। भारत में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता कार्यों में श्रम मानकों और कानूनी विनियमन को सुनिश्चित करने में राज्य की प्रतिबद्धता की कमी के कारण, संघीकरण और वकालत के माध्यम से सामूहिक लामबंदी बातचीत के लिए एकमात्र स्थान प्रतीत होता है। संघ की सदस्यता ने स्वच्छता कर्मचारियों को उच्च वेतन, सुरक्षा उपकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग करने में मदद की है। ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए श्रमिकों को श्रमिक-नेतृत्व और श्रमिक-संचालित सहकारी समितियों में संगठित करने का भी एक संभावित मॉडल के रूप में सुझाव दिया गया है (श्रुति और मजूमदार, 2021)।

इस प्रकार, इन क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों की मदद से संघीकरण के महत्व पर चर्चा की जानी चाहिए। कचरा प्रबंधन श्रमिकों के रूप में पंजीकरण, अच्छा आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, और कचरा प्रबंधन प्रणाली का विकेंद्रीकरण कुछ ऐसी मांगें हैं जिन्हें संगठित श्रमिकों द्वारा रखा जा सकता है। अब समय

आ गया है कि राज्य टिकाऊपन सुनिश्चित करने में कचरा प्रबंधन श्रमिकों द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका को पहचाने और निजी लाभ चाहने वाली संस्थाओं को नियंत्रण सौंपने के बजाय सीधे उनकी जरूरतों को पूरा करके श्रमिकों की गरिमा की रक्षा करे। भारत में कचरा श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर एक रिपोर्ट में कचरा श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित नीतिगत सिफारिशें शामिल थीं। श्रमिकों तक स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के प्रसार के साथ-साथ कचरा श्रमिकों की प्रत्येक श्रेणी के विशेष संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, मातृत्व अधिकार, पानी और स्वच्छता जैसे बुनियादी अधिकार, और सभी श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ नामांकन, और सेवाओं तक पहुंच से दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को अलग करने का भी सुझाव दिया गया था (लक्ष्मी एट अल।, 2021)।

इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष औपचारिक नीति निर्माण के दायरे में कचरा प्रबंधन श्रमिकों को शामिल करने की सख्त आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दैनिक श्रम और जीवन की वास्तविकताओं पर विचार किया जाए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक जाति समाज में, समूह की पहचान व्यवसायों और अंतर्निहित श्रम संबंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अंततः भविष्य की सामाजिक गतिशीलता के लिए बच्चों के लिए वैकल्पिक रोजगार और शिक्षा के रास्ते सुनिश्चित करके इसे खत्म करने की आवश्यकता है। जबकि अध्ययन घर-घर कचरा प्रबंधन कार्य में लगी महिला आदिवासी कार्यकर्ताओं पर केंद्रित है, यह कचरे की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलता है। इस तरह के शोध अध्ययन से नीति निर्माताओं और नगरीय निकायों को श्रमिकों के लिए अधिक समावेशी नियम और नीतियां तैयार करने में सहायता मिलेगी। अमेरिका में 1968 में मेम्फिस में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गये। उनके धरना चिन्हों पर लिखा था, "मैं एक आदमी हूं", समान व्यक्तित्व की मान्यता का दावा जिससे अन्य सभी अधिकार आधारित दावे उत्पन्न होते हैं। अब समय आ गया है कि हम क्षेत्र की बदलती राजनीतिक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कचरे के ऐतिहासिक रूप से अमानवीय काम में लगे श्रमिकों के व्यक्तित्व को समझें और उनके अधिकारों को सुरक्षित करें।

REFERENCES

Agarwala, R. (2016). Redefining Exploitation: Self-Employed Workers' Movements in India's Garments and Trash Collection Industries. *International Labor and Working-Class History*, *89*, 107–130. http://www.jstor.org/stable/43956682

Ahmedabad Municipal Corporation. (2020). *Brief Note on Solid Waste Management Department*. https://ahmedabadcity.gov.in/Images/_SWM%20Dept_SWM%20BREIF%20NOTE%20IN%20ENGLISH.pdf

Ahmedabad Municipal Corporation. (2020). *Making Ahmedabad The Cleanest Mega City of India*. https://ahmedabadcity.gov.in/Images/_SWM%20Dept_SWM%20DEPT_BREIF%20PPT_ENGLISH.pdf

Brook, D. (2014). *Can Waste-Picking Be a Good Career?* Nextcity.org. https://nextcity.org/features/pune-india-waste-pickers-union

Campbell, S. (2018). Migrant Waste Collectors in Thailand's Informal Economy: Mapping Class Relations. *European Journal of East Asian Studies*, *17*(2), 263–288. https://www.jstor.org/stable/26572846

Chadha, K. (2020). *INFORMAL WASTE WORKERS: THE ISSUE OF FORMALISATION*. Social Policy Research Foundation. https://sprf.in/wp-content/uploads/2021/02/24.07.2020_Informal-Waste-Workers_-The-Issue-of-Formalisation.pdf

Chandvankar, R. (2021, December). *Redefining Caste: A Study of Dalit Women's Sanitation Labor and Generational Aspirations*. University of Oregon Division of Graduate Studies. https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/27060/Chandvankar_oregon_0171A_13193.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch. (2022, December 29). *Govt of India "not taking cognizance" of life, dignity of waste collectors: DASAM meet*. Counterview . https://www.counterview.net/2022/12/govt-of-india-not-taking-cognizance-of.html

Dash, D. K. (2023, March 29). Centre identifies 70K women influencers contributing big to govt's Garbage Free City mission. *The Times of India*. https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-identifies-70k-women-influencers-contributing-big-to-govts-garbage-free-city-mission/articleshow/99097856.cms?from=mdr

Dr Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches (BAWS) (various years), Volumes 1 to 21, Government of Maharashtra, Mumbai

Eswaran, A., & Hameeda , C. (2013). The Waste Picking Community: Some Issues and Concerns. *Economic & Political Weekly* , *48*(22). https://www.epw.in/journal/2013/22/web-exclusives/waste-picking-community-some-issues-and-concerns.html

Fulwani, D., & Chandel, D. (2019). Occupational Impact On Health Of Women Rag Pickers Of Ahmedabad. *IJAR - Indian Journal of Applied Research*, *IX*(II). https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-(IJAR)/article/occupational-impact-on-health-of-women-rag-pickers-of-ahmedabad/MTY5MTM=/?is=1&b1=269&k=68

Josyula, L. K., Murthy, S., Karampudi, H., & Garimella, S. (2022). Isolation in COVID, and COVID in Isolation—Exacerbated Shortfalls in Provision for Women's Health and Well-Being Among Marginalized Urban Communities in India. *Frontiers in Global Women's Health*, *2*. https://doi.org/10.3389/fgwh.2021.769292

Kanekal, S. (2019). *Challenges in the Informal Waste Sector: Bangalore, India*. Penn Institute for Urban Research . https://penniur.upenn.edu/uploads/media/03_Kanekal.pdf

Kumar, A., & Agrawal, A. (2020). Recent trends in solid waste management status, challenges, and potential for the future Indian cities – A review. *Current Research in Environmental Sustainability*, *2*, 100011. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2020.100011

Lakshmi, J. K., Nakkeeran, B., Murthy, S., Whittaker, L., Ramanamurthi, B., Sai, V., Saligram, P. S., & Garimella, S. (2021, August). *Health and well-being of waste workers in India*. ARISE. https://

REFERENCES

www.ariseconsortium.org/wp-content/uploads/2021/08/arise-health-wellbeing-of-waste-workers-policybrief-f220721.pdf

Luthra, A., & Monteith, W. (2021). *Of market vendors and waste collectors: Labour, informality, and aesthetics in the era of world-class city making.* Antipode, 55: 1068-1088

Madhav, R. (2010). *Untapped Potential: Securing livelihoods dependant on "Waste" A Review of Law and Policy in India* . https://swachcoop.com/pdf/WPandLaw.pdf

Mahanty, G. K., & Sugathan, S. (2018, June 27). *Under Ahmedabad's Mounting Garbage, It's the Migrant Worker Who Is Crumbling*. The Wire. https://thewire.in/labour/ahmedabad-garbage-air-pollution-migrant-workers

Majumdar, S. (2023, May 8). *India Is Home to 169 Billionaires, but These Children Still Forage Through Trash*. Pulitzer Center. https://pulitzercenter.org/stories/india-home-169-billionaires-these-children-still-forage-through-trash

Mistry, J., Mohan, D., Agarwal, S., Ayreen, S., & Mehtani, T. (2020, October). *Wasted Lives: The Tragedy of India's "Safai Mitra."* The Wire. https://thewire.in/rights/india-waste-pickers-covid-19-lockdown

Oates, L., Sudmant, A., Gouldson, A., & Gillard, R. (2018). *Reduced waste and improved livelihoods for all: Lessons on waste management from Ahmedabad, India*. https://newclimateeconomy.report/workingpapers/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/CUT18_Leeds_Waste_Final-1.pdf

Padode, T. (2022, January). *Ahmedabad civic body chooses Indore model for waste management | Smart Cities Council*. Www.smartcitiescouncil.com. https://www.smartcitiescouncil.com/article/ahmedabad-civic-body-chooses-indore-model-waste-management

Pal, A. (2023, October 9). *The Swachh Bharat Abhiyan: For Whom and By Whom?* Round Table India. https://www.roundtableindia.co.in/the-swachh-bharat-abhiyan-for-whom-and-by-whom/

Press Trust of India . (2023, November). *In Madhya Pradesh's Tribal-Dominated Jhabua, Blame Game Over Migration*. NDTV.com. https://www.ndtv.com/india-news/in-madhya-pradeshs-tribal-dominated-jhabua-blame-game-over-migration-4567929

Rajendra, A. (2022). Skills in 'unskilled' work: a case of waste work in Central India. Third World Quarterly. 1-19. 10.1080/01436597.2022.2086115.

Ramachandran, S. K. (2023, November 16). *Madhya Pradesh election: Jhabua becomes site of tussle for the tribal vote*. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/india-news/madhya-pradesh-election-jhabua-becomes-site-of-tussle-for-the-tribal-vote-101700076121792.html

Sannabhadti, R. (2019). *Struggles for Everyday Space: Scrap Pickers in Ahmedabad* . CEPT University. https://mdl.donau-uni.ac.at/binucom/pluginfile.php/405/mod_page/content/38/P4_WP2.5_Case_Study_4_ScrapPickers_CEPT.pdf

Self Employed Women's Association (SEWA). (2010). Working in the Waste and Recycling Sector: Opportunities and Challenges for Green Jobs . In *International Labour Organization*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-new_delhi/documents/meetingdocument/wcms_142513.pdf

Sharma, J. (2023, November 15). *Sectoral Trajectory of Waste Management in India*. Indiachapter.in. https://indiachapter.in/index.php?/user/article/2/20/96

Shruti , I., & Majumdar, M. (2021, January). *How caste oppression is institutionalised in India's sanitation jobs*. Scroll.in. https://scroll.in/article/984297/how-caste-oppression-is-institutionalised-in-indias-sanitation-jobs

Sinha, P. (2016, September). *Ahmedabad: Update on Strike by Safai Kamdars of AMC*. Sanhati.com. http://sanhati.com/articles/17449/

Sreevatsan, A. (2020, June 4). *Cities in Gujarat first to feel the pinch of migrant exodus*. Mint. https://

www.livemint.com/news/india/cities-in-gujarat-first-to-feel-the-pinch-of-migrant-exodus-11591293714054.html

White, B. H. (2015, October 7). The politics of waste management. *The Hindu*. https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-politics-of-waste-management/article7731264.ece

Wittmer, J. (2021). "We live and we do this work:" Women waste pickers' experiences of wellbeing in Ahmedabad, India. World Development, Vol 140: 105253. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105253

Wittmer, J. (2023a). Dirty work in the clean city: An embodied Urban Political Ecology of women informal recyclers' work in the "clean city." *Environment and Planning E: Nature and Space*, 251484862211023. https://doi.org/10.1177/25148486221102374

Yadav, S. (2020, March 27). A long walk home for 30,000 tribal workers in M.P. *The Hindu*. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/a-long-walk-home-for-30000-tribal-workers-in-mp/article31186087.ece

Wittmer, J. (2023b). "I salute them for their hard work and contribution": Inclusive urbanism and organizing women recyclers in Ahmedabad, India. Urban Geography, 44(9): 1911-1930.

https://doi.org/10.1080/02723638.2023.2192560

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1: मानचित्रों और चार्टों की सूची

चित्र 1 - कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र को दर्शाता है

चित्र 2 - कचरे की मूल्य श्रृंखला को दर्शाता है

चित्र 3 - अहमदाबाद में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण को दर्शाया गया है

चित्र 4 - सूरत में ज़ोन-वाइज स्थानांतरण स्टेशन

मानचित्र 1 - दाहोद और जाबुआ से अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत तक प्रवासन गलियारा

चार्ट 1 - उत्तरदाताओं की स्रोत स्थिति

चार्ट 2 - उत्तरदाताओं के स्रोत जिले

चार्ट 3 - उत्तरदाताओं की आयु सीमा

चार्ट 4 - उत्तरदाताओं के शिक्षा स्तर

चार्ट 5 - उत्तरदाताओं के कार्य के वर्षों

चार्ट 6 - अनुबंध पर रखे गए जोड़ों के मासिक वेतन

चार्ट 7 - श्रमिकों को भुगतान के तरीके

चार्ट 8 - उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा

चार्ट 9 - एक दिन के दौरान काम के घंटे

चार्ट 10 - उत्तरदाताओं को प्राप्त सुरक्षा प्रावधान

चार्ट 11 - उत्तरदाताओं की आवास स्थिति

चार्ट 12 - श्रमिक परिवारों द्वारा भुगतान किया गया मासिक किराया

चार्ट 13 - शौचालय तक पहुंच

CLRA

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (सीएलआरए) भारत की विशाल अनौपचारिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह अनौपचारिक क्षेत्र में काम की स्थितियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए अनुसंधान करता है और इसके बाद राज्य के साथ नीतिगत वकालत करता है ताकि श्रमिकों को उनका उचित अधिकार प्राप्त हो सके। केंद्र ने मौसमी प्रवास धाराओं के दस्तावेजीकरण में अग्रणी काम किया है जो कृषि, ईंट भट्टों, भवन और निर्माण जैसे श्रम गहन उद्योगों को श्रमिकों को उपलब्ध कराती हैं। इसके कार्य ने श्रमिकों को संगठित करने के एक वैकल्पिक प्रतिमान को विकसित किया है जो श्रमिकों के निरंतर आंदोलन, बिचौलियों की महत्वपूर्ण भूमिका, उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति और श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखता है।

रोज़ा लक्ज़मबर्ग फाउंडेशन

रोजा लक्जमबर्ग स्टिफ्टंग (आरएलएस) जर्मनी स्थित फाउंडेशन है जो महत्वपूर्ण सामाजिक विश्लेषण और नागरिक शिक्षा के विषयों पर दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रहा है। यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य समाज के सदस्यों और निर्णय निर्माताओं को ऐसी व्यवस्था के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। अनुसंधान संगठनों, सामाजिक मुक्ति के लिए काम करने वाले समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसे मॉडल विकसित करने की पहल में समर्थन दिया जाता है जिनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की क्षमता होती है।

अस्वीकरण

जर्मनी के संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संघीय मंत्रालय के फंड से रोजा लक्जमबर्ग स्टिफ्टंग द्वारा प्रायोजित। इस प्रकाशन या इसके कुछ हिस्सों का उपयोग दूसरों द्वारा निःशुल्क किया जा सकता है, जब तक वे मूल प्रकाशन का उचित संदर्भ प्रदान करते हैं। प्रकाशन की सामग्री पार्टनर सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन की जिम्मेदारी है, और जरूरी नहीं कि यह आरएलएस की स्थिति को प्रतिबिंबित करे। यह अध्ययन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं है और केवल निजी प्रसार के लिए है।